

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 अगस्त, 1988

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 24 अगस्त, 1988

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)1
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)26
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(3)30

ध्यानकर्षण प्रस्ताव:-	
हरियाणा राज्य में उग्रवादियों की गतिविधियों से लोगों में आतंक होने संबंधी	(3)31
वक्तव्य-	
(i) मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(3)32
(ii) राजस्व मंत्री द्वारा हरियाणा में वर्षा तथा बाढ़ से फसल तथा सम्पत्ति को क्षति होने संबंधी	
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(3)41
सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र	(3)42
बिलज-	
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए 1न (नं0 3) बिल, 1988	(3)42
दि हरियाणा गुड कन्डक्ट प्रिजनर्ज (टैम्पोरेरी रिलीज) बिल, 1988	(3)44
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिड अमैडमैट) बिल, 1988	(3)53

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 24 अगस्त, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रांत: 9-30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बरसाहेबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 576

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री प्रदीप कुमार चौधरी इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 582

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र कुमार मदान, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 594

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री रघु यादन इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

**Corruption charge against the Employees of Transport
Department**

***599 Sh. Ranjit Singh:** Will the Minister of state for Transport be pleased to state the names of employees from class-1 to class-IV of Transport department against whom the corruption charges were leveled during the last tow years i.e. up to 30-06-1988; if so, the District wise and depot wise number of these cases decided/pending for finalization?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मवरी सिंह): हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रति दिन लगभग 9.50 लाख किलोमीअर दूरी तय करती है जिनमें लगभग 12 यात्री सफर करते है। बेड़े की संख्या 3188 है। परिवहनपरिचालन के दौरान जो केसिज कम मूल्य का टिकट देने के या पुनः जारी करने के या बिना टिकट यात्रा करने के पकड़ में आते है, उसमें दोशी परिचालकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती हैं पिछले दो वर्षों में (30.6.88 तक) ऐसे कर्मचारियों की डिपो अनुसार व जिला अनुसार विवरण एकत्रित करने के लिए और अधिक समय की आव यकता है। जो यात्री जानबूझ कर टिकट बिना लिए यात्रा करते है, उन्हे जुर्माने से दंडित किया जाता है परिवहन परिचालन के स्टाफ के अतिरिक्त क्लास-1 से क्लास-IV के कर्मचारी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पिछले दो वर्षों में 30.06.1988 तक लगाए गए है वे जिनके केसों के निर्णय हो चुके है या लम्बित पड़े है, उनकी जिलावार व डिपोवारसूची सदन के पटल पररखी जाती है।

सूची

क्रम	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	जिला	डिपो	केस की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बिजेन्द्र सिंह	III	भिवानी	भिवानी	लम्बित
2	श्री सुरेन्द्र सिंह	III	रोहतक	रोहतक	—सम—
3	श्री कंवर सिंह	III	रोहतक	रोहतक	—सम—
4	श्री मं ॥ राम	III	रोहतक	रोहतक	—सम—
5	श्री पवन कुमार	III	रोहतक	रोहतक	—सम—
6	श्री राम कुमार	III	रोहतक	मुख्यालय	—सम—
7	श्री सुदर्शन	III	रोहतक	मुख्यालय	—सम—
8	श्री चन्द्रभान	IV	रोहतक	मुख्यालय	निर्णय हो चुका है।
9	श्री सुरेन्द्र सिंह	IV	रोहतक	मुख्यालय	—सम—
10	श्री सत नारायण	III	करनाल	करनाल	—सम—
11	श्री हेम राज	III	करनाल	करनाल	—सम—
12	श्री मदन लाल	III	करनाल	करनाल	6 केसों में से एक का

					निर्णय हो चुका है।
13	श्री सुनेहरा राम	III	करनाल	करनाल	लम्बित
14	श्री मोहन लाल	III	करनाल	करनाल	—सम—
15	श्री सत नारायण	III	करनाल	करनाल	—सम—
16	श्री मखन लाल	III	गुडगांव	गुडगांव	—सम—
17	श्री कृष्ण लाल	III	गुडगांव	मुख्यालय	—सम—
18	श्री जसवीर सिंह	III	गुडगांव	मुख्यालय	—सम—
19	श्री बलदेव सिंह	III	सोनीपत	मुख्यालय	—सम—
20	श्री होरियार सिंह	III	सोनीपत	मुख्यालय	—सम—
21	श्री राम निवास	III	सोनीपत	मुख्यालय	—सम—
22	श्री ओम प्रकाश आर्य	III	सोनीपत	मुख्यालय	—सम—
23	श्री बलबरी सिंह	IV	सोनीपत	मुख्यालय	निर्णय हो चुका है
24	श्री रत्न लाल	III	सोनीपत	मुख्यालय	लम्बित

25	श्री साधु राम	III	अम्बाला	मुख्यालय	—सम—
26	श्री गुरु प्रसाद	III	अम्बाल	मुख्यालय	—सम—
27	श्री कंबलजीत सिंह	III	अम्बाल	मुख्यालय	—सम—
28	श्री प्रेम कुमार	IV	हिसार	हिसार	—सम—
29	श्री मेवा सिंह	IV	हिसार	हिसार	—सम—
30	श्री राम सिंह	IV	हिसार	हिसार	—सम—
31	श्री मन्पुरा	IV	हिसार	हिसार	लम्बित
32	श्री ऋशि कुमार	III	हिसार	हिसार	—सम—
33	श्री जोगिन्द सिंह	III	हिसार	हिसार	—सम—
34	श्री राय बहादुर	III	हिसार	हिसार	—सम—
35	श्री बहादुर सिंह	III	हिसार	हिसार	—सम—
36	श्री मनोहर लाल	III	हिसार	हिसार	—सम—

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कई केसिज जैसे टिकट हेरी फेरी के केसिज है ओर जो कन्डकटरो के खिलाफ होते है, डिसाईड नही होते और लम्बित पड़े रहेते है। लेकिन क्या

मंत्री जी बताएंगे कि जनरल मैनजेजर, रोडवेज ओर अन्य बड़े अधिकारियों के खिलाफ कितने ऐसे केस पड़े है जो कि डिसाईड नहीं हुए और लम्बित है?

श्री धर्मवीर सिंह: क्लास-I और क्लास-IV के जितने अधिकारी/कर्मचारी है, उनके खिलाफ इस प्रकार के कोई केसिज नहीं हैं

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इनके नोटिस में यह बात है कि रोडवेज की वर्क गापों में सब-स्टैण्डर्ड माल आ जाता है और इनमें काफी गड़गड़ी होती है क्या इनके पास ऐसी कोई रिक्वायत आई, जिसमें टिकट रि-इस्यु कर दिये गये हो यदिहां तो ऐसे कितने केसिज है और सरकार इन केसों पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री धर्मवीर सिंह: मैटीरियल के सब-स्टैण्डर्ड होने की कोई रिक्वायत हमारे नोटिस में नहीं आई है। जहां तक टिकट रि-इस्यु का संबंध है, इस बारे में भिवानी में एक, रिवाड़ी में 3 और हिसार में एक मामला नोटिस में आया है। इन केसों पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए दोशी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है।

श्री मेहेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनके नोटिस में यह बात है

कि हरियाणा राज्य में कई बसें ऐसी चल रही हैं जिनसे महीने में 25 रुपये की इनकम नहीं होती?

श्री धर्मवीर सिंह: ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जील राय बहादुर को हरा कर यहां आये हैं जिनके समय में रोडवेज घाटे में चल रही थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब से ये मंत्री बने हैं, इस महकमे में कितना घाआ या फायदा हुआ?

श्री धर्मवीर सिंह: स्पीकर सर, मैं इस साल का अप्रैल से जुलाई, 1988 तक का ब्यौरा इन्हें बताना चाहूंगा। इन चार महीनों की अवधि में ही 95 प्रतिशत से अधिक मुनाफा हुआ है। (थम्पिंग)

Recommendations of Eradi Commission

***616 Sh. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the state Government has received a copy of the report of Justice Eradi Commission in regard to the division of waters under the Punjab accord; if so, the action taken or proposed to be taken on the recommendations of the commission?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): The report of the Ravi and Beas Waters Tribunal has been received. The State Government has considered the report and made a reference to the Tribunal under Section 5(3) of the Interstate Water Disputes Act, 1956. The matter is

under consideration of the Tribunal and its further report is awaited.

श्री मंगल सैन: क्या हमारे माननीय सिचाई मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेगे कि ट्रिब्यूनल ने जो रिपोर्ट दी है, उसके सेलियैट फीचर्ज क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इराडी ट्रिब्यूनल ने अपने रिपोर्ट 20.05.87 को दी। उस रिपोर्ट में दो बातें हरियाणा प्रांत के लिए बहुत ही इन्पोटेंट हैं। एक तो इराडी ट्रिब्यूनल ने होल्ड किया है कि Haryana is a part of Indus basin और सैकिन्डली पंजाब जो क्लेम कर रहा था कि रावी व्यास के पानी पर उनका ही हक है being a riparian state हरियाणा का नहीं, that claim of Punjab has been rejected by the Eradi Tribunal. इसके अलावा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है हालांकि उनको रैफरेंस नहीं था लेकिन अपनी रिपोर्ट के कनक्लूडिंग पैरे में लिखा है कि एफर्ट्स किये जायें कि एस० वाई० एल० कैनल जल्द से जल्द कम्प्लीट हो ताकि यह पानी हरियाणा प्रांत को मिल सके। हरियाणा प्रांत को टोटल पानी में से 3.83 एम० ए० एफ० पानी देने का इराडी ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिचाई तथा बिजली मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने ट्रिब्यूनल के समाने कितने पानी का क्लेम किया और कितना दिया गया?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इराडी ट्रिब्यूनल को जो रैफरेन्स भेजा गया था, वह राजीव लौगोवाल के बची जो एकोर्ड साइन हुआ था, उसकेंतहत भेजा गया था। पानी का क्लेम हमारा काफी था और हमारी उसमें मेन बात थी कि पानी नीड बेसड होना चाहिए। हमें पानी की अधिक जरूरत है इसलिए हमें अधिक मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने जो फांडिग दी है। उसमें 3.83 एम0 ए0 एफ0 हरियाणा को और 5 एम0 ए0 एफ0 पंजाब को रिकमैड किया है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन-जिन प्वायंट पर इराडी कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उन प्रत्येक प्वायंट पर हरियाणा सरकार का क्या स्टैन्ड है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जिन-जिन प्वायंट्स पर हमारे हम में फैसला हुआ है वह तो मैं बता दिये। हमारा मेन प्वायंट था कि Haryana is a part of Indus basin जिस पर हरियाणा के हक में फैसला हुआ है और पंजाब के खिलाफ हुआ है। पंजाब का यह क्लेम था कि पंजाब ही अकेला इस पानी के लिए एनटाइटल है Being a riparian state. That claim of Punjab has been rejected by the Eradi Tribunal दूसरे, जो 3.83 उम0 ए0 एफ0 पानी हमें ऐलोकेट हुआ है, उसको हमने कम माना है। अब हमने इन्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट ऐक्ट, 1956 की धारा 5 सब-क्लास 3 के तहत रैफरेन्स अडाला है कि बिलों रिग स्टेट्स जितना भी पानी

अवेलेबल है, वह सारे का सारा हमें मिलना चाहिए। यह रैफरेन्स हमने डाला है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने मंत्री महोदय से सवाल यह किया था कि कितने पानी की डिमान्ड की थी और आपने कह दिया कि बहुत पानी की डिमान्ड की थी। मैं यह पूछ रहा हूँ कि नीड बैस्ट कितना था और कितने मैयरमैट है? दूसरे जो हमने इन्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट ऐक्ट, 1956 की धारा 5 की सब क्लॉज 3 के तहत रैफरेन्स डाला है, उस फैसला कब तक होने की आशा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: माननीय सदस्य को आपे द्वारा बताना चाहिए कि हमने टोटल क्लेम कितना किया है उसकी ऐग्जैक्ट फिगर नहीं है कि हमें इतना ही मिलना चाहिए। हमने अलग-अलग हिसाब से क्लेम किया है कि हमारी इतनी इरीगेशन है, इतनी हमारी क्वायरमेंट है। हमने कहा है कि बल्क ऑफ वाटर हमें चाहिए ऐसा रैफरेंस हमने डाला है।

श्री मंगल सैन: मैंने मैयरमैट के बारे में पूछा है उसका जबाब नहीं आ रहा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: ऐग्जैक्ट फिगर नहीं दी सकती। ट्रिब्यूनल में 10.10.88 को नैक्सट डेट लगी हुई है। तीन-चार डेट्स लग चुकी हैं हर तारीख पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और

पंजाब सरकार आगे की तारीख मांग लेते हैं। कि अभी यह फैसला नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि पंजाब में हालात नार्मल नहीं हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस ट्रिब्यूनल की ओर से पहले जो फ्लो औफ वाटर की मैयूरमैट हुई थी, उसमें जितनी क्वांटिटी की पैमाइं की गयी थी, उसी आधार पर उसमें घटत-बढ़त मानते हैं या उसमें कम घटत-बढ़त मानते हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है, उसने उसमें यह कहा है कि रिंग स्टे इन से अब टोटल जो पानी अवेलेबल है, वह 1.11 एम0 ए0 एफ0 है उस 1.11 एम0 ए0 एफ0 वाटर में से कुछ पानी हरियाणा को ऐलोकेट किया गया है और कुछ पंजाब को ऐलोकेट किया गया है। इस प्राकर से पंजाब का हिस्सा 4.22 से बढ़ाकर 5.00 एम0 ए0 एफ0 किया गया है। और हरियाणा का हिस्सा 3.50 से बढ़ाकर 3.83 एम0 ए0 एफ0 किया गया है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, कुछ जवाब तो आ गया है लेकिन मैं इस बारे में कुछ क्लैरीफिके इनप लेना चाहता हूँ। जिस वक्त इराडी कमी इन ने फैसला दिया, उस वक्त अखबारों में एक खरबर छपी थी। उस खबर की बिना पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो हमारा क्लेम था और हमारा हक बनता था कि इतना पानी में मिलना चाहिये, उस हक के मुताबिक वह

पानी में मिला है या नहीं? यह फैसला तो हमारे हक में गया है जैसे कि अखबारों में कहा गया था कि सरकार उसका विरोध कर रही थी। लेकिन हमारे अफसर साहेबान ने इनका यह कन्विन्स किया कि यह फैसला हमारे हक में गया है।

श्री अध्यक्ष: आप वैसे ही प्रिज्यूम कर रहे हो। आप सीधा सवाल करे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह फैसला हमारे हक में गया है या नहीं गया है?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, हमारे मैम्बर साहब जो सामने बोल रहे है, यह कांग्रेस पार्टी के लीडर है। यह सवाल इनको हमसे नहीं करना चाहिये था बलिक केन्द्र सरकार से करना चाहिये था। हमार स्टैड अखबारों में भी आया है प्राईम मिनिस्टर ने कहा है कि हरियाणा सरकार ट्रिब्यूनल को मानती नहीं है इसलिये हम कुछ नहीं कर सकते। यह बहानेबाजी है। चार दफा हम प्राईम किनस्टर से मिल चुके है। चार लैटर लिख चुके है। चार दफा हमारे इरीगे इन एंड पावर मिनिस्टर मौके पर जा चुके है पहली दफा जब मैं प्राईम मिनिस्टर साहब से मिला तो उनहोने कहा कि आप तो इराडी कमी इन को नहीं मानते, कैसे फैसला हो? मैंने उसका जवाब दिया कि अगर इराडी कमी इन का फैसला माना होता तो मैं आपके सामने कैसे बैइ सकता? इराडी कमी इन का फैसला बंसी लाल और भजन लाल ने

माना था, उसका हश्र आपके सामने है। जहां तक इराडी कमी इन का ताल्लुक है, हम इस फ़ैसले को मानते हैं कि उन्होंने हमें पानी का हिस्सेदार बनाया। यह हरियाणा के हक में है। यह बात मैं हाउस में भी कह चुका हूँ और गवर्नर ऐड्रेस में भी यह बात आ चुकी है। लेकिन पानी की मिकदार हमें थोड़ी मिल रही है। जैसे इरीगे इन एंड पावर मिनिस्टर ने कहा, पानी की मिकदार पूरी चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने इसको पोलिटीकल इ टू बना रखा है। जहां तक डा० मंगल सेन जी ने सवाल का सम्बन्ध है, ये सवाल तो यहां करते हैं लेकिन जब हम न्याय युद्ध 23 मार्च को लड़ रहे थे और उसमें 10 लाख आदमी हाजिर थे, हमारे डाक्टर महोदय ने वहां पर कोई काम नहीं किया। स्टेज पर तो आ गये थे लेकिन एक कार्यकर्ता भी उस कान्फ्रेंस में तैयारी के लिये नहीं भेजा था। अब यह है कि अगर केन्द्र सरकार नहीं मानी तो इसके लिये एक और न्याय युद्ध भुरू किया जायेगा। उसमें डा० साहब का पता लग जायेगा। (व्यवधान व भाोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी क्या बात करते हैं? हमारे तो हजारों वहां पर मौजूद थे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी देवी लाल: ये पांच थे। कार्यकर्ता एक भी नहीं था। (व्यवधान व भाोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकरसाहब, यह फ़ैक्ट नहीं है.....

Mr. Speaker: No. no. It clinches the issue. The entire matter has been explained. Next question.

(At this state some members rose to ask supplementaries)

Mr. Speaker: Please take your seats. No more supplementaries on this question as I have already called the next question.

Opening of Model School in Each constituency

***577 Sh. Durga Dutt Atri:** Will the Minister for education be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open Model Schools in each constituency in the State; and

(b) if so, the details thereof togetherwiththe time by which the said proposal is likely to mature?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि शिक्षा के स्तर में समानता लाने के लिए यह जरूरी नहीं कि देहात में भी मॉडल स्कूल खोले जाए?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, हमारे यहां मौडल स्कूल का कोई कंसैप्टान नहीं हैं इसलिए हर स्कूल में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए कौर्षिा की जा रही है ताकि सब जगह एक जैसी शिक्षा दी जा सके।

श्री रणजी सिंह: मंत्री जी ने बताया है कि हरियाणा मतेँ मौडल स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं हैं स्पीकर साहब, गाँवों के अन्दर जितने गवर्नमेंट स्कूल है, उन सब की हालत बहुत खराब है। जो मौडल स्कूल में शिक्षा दी जाती है, उसके मुकाबले में गाँवों के स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, उसका स्तर बहुत घटिया है। मौडल स्कूल खोलने का प्रोजैक्ट बहुत लम्बा चौड़ा नहीं है। यह नहीं कि इसके लिए कोई पचास लाख या एक करोड़ रूप्या चाहिए। दस पन्द्रह लाख रूप्ये में हरेक कांस्टीचुऐन्सी में टेस्ट के तौर पर एक स्कूल खोल दिया जाए। स्पीकर साहब, गाँवों में जो स्कूल है उनमें शिक्षा का स्तर घटिया होने के कारण ही लोगो ने कौनवैन्ट स्कूल या पब्लिक स्कूल घर—घर में खोल रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इस बारे में सरकार विचार करेगी?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, फिलहाल इस तरह के स्कूल खोलने की सरकार की कोई तजवीज नहीं हैं अगर मेरे साथी कोई सजैान या कोई कंक्रीट प्रोजैक्ट देगे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी समाजवादी जनता दल में मिलने जा रही है ओर उसके मैनिफैस्टों में सब को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार ओर पढ़ाई देने का प्रावधान है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी जनता दल के अन्दर मौडल स्कूल या पब्लिक स्कूल बन्द करके सब बच्चों को समान ऐजुके ान दिए जाने की पौलिसी है?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): समाजवादी जनता दल की सरकार काय हो लेने दो, उसके बाद बताएंगे।

कामरेड हरपाल सिंह: मंत्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा में मौडल स्कूल खोने का कोई विचार नहीं है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी स्कूलज की बिल्डिंगज है, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है, बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी मैटीनैस का कोई इन्तजाम करने का सरकार का विचार है?

श्री खुरशीद अहमद:स्पीकर साहब, जिनते स्कूलज की बिल्डिंगज की मरम्मत की जरूरत होती है उसके लिए बाकायदा हर साल कुछ पैसा पी0 डब्ल्यू0 डी0 को उनकी मरम्मत के लिए दिया जाता है कुछ पैसा टीचर्ज पैरेंटस एसोसिए ान के जरिए इकट्ठा होता है। उस पैसेको वे अपने आप खर्च करते है। और स्कूलज की मरम्मत कराते है। इस साल जहां फ्लड से स्कूल की बिल्डिंग की

ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको असास करवा रहे हैं और उसके बाद जहां जरूरत होगी वहां खातिरवाह मरम्मत की जाएगी।

चौधरी कुलबरी सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इस साल दसवी का रिजल्ट बहुत खरबा आया है। कई जगह पर रिजल्ट जीरो परसैन्ट है और कहीं पर एक परसैन्ट आया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिजल्ट को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार करेंगे?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, इस साल हमारी कोशिश यही थी कि बच्चे खुद इम्तिहान में लिखें क्योंकि बच्चों ने खुद पेपर लिखे इसी वजह से यह रिजल्ट जीरो परसैन्ट रहा। बच्चे खुद पढ़ने-लिखने की तरफ ध्यान न दें और टीचर्स और बच्चों को यह पता लग जाए कि अब नकल से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा इसलिए इस दफा विधेयक ध्यान नकल को रोकने की तरफ दिया गया। इस बारे में मैंने रिपोर्ट मंगवाई और जो कुछ रिपोर्ट मुझे मिली है, उससे पता लगता है कि इसबार नकल नहीं हुई। स्पीकर साहब, उसी का यह नतीजा है। भारत में यह रिजल्ट खराब होना लालिमी था। बहुत से बच्चे और टीचर्स यह विचार कर रहे थे कि पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नकल से ही काम चल जाएगा। लेकिन इस साल उनका यह स्वप्न सही नहीं निकला। स्पीकर साहब, जहां के रिजल्ट खराब हैं, वहां पर पूरी तरह से छानबीन करके इन्तजाम किया जाएगा।

श्री महा सिंह: स्पीकर सहब, मौडल स्कूल और पब्लिक स्कूल के नाम से कुछ प्राइवेट लोगों ने दुकाने खोली हुई हैं और वे शिक्षा के नाम पर लोगों से धन लूट रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान है कि इन दुकानों को बन्द कर दिया जाए?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, इनकी यह बात जायज है कि बहुत से स्कूलों में, कहीं मौडल स्कूलों का नाम दे रखा है। कहीं पब्लिक स्कूल बना रखे हैं, लोगों से इन्हीं नामों के कारण ज्यादा फीस ऐंठी जा रही है लेकिन रिकार्ड में केवल वही राशि होती है जोकि ऐक्युअल फीस की होती है। कानूनी तौर पर इसी कारण से वे पकड़ में नहीं आते। यह मुद्दा सरकार के विचारधीन है। कि किस तरीके से कानून में तरमीम करके ऐसे लोगों को काबू किया जा सके। जिससे कि लोगों से कानून के मुताबिक ही फीस ली जा सके, ज्यादा फीस न ली जा सके।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्षा के कारण जिन स्कूलों की छतें गिर गयी हैं, क्या ऐसे स्कूलों के बच्चों के लिए सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार रखती है ताकि बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा जा सके?

श्री खुरशीद अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि फ्लड्ज के कारण जहां-जहां नुकसान हुआ है, उसका फौरी तौर पर जायजा ले रहे हैं और जो भी आल्टरनेटिव इन्तजाम बच्चों की पढाई के लिए हो पायेगा, वह हम करेगे।

श्री आत्मा राम गोदारा: स्पीकर साहब, सरकार की यह बात तो ठीक है कि हरियाणा में परीक्षाओं में नकल रोकी गयी है और यह पता भी लगेगा कि अब इसके क्या नतीजे होंगे लेकिन जहां तक हमें वि वास है कि इसके अच्छे ही नतीजे निकलेगे। इसके साथ-साथ मैं एक बड़ी आव यक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हरियाणा के बच्चों को इंजीनियरिंग कालेजिज में सी० बी० एस० ई० के बच्चों की निस्बत ऐडमिशन नहीं मिलती हैं इसका कारण यह है कि सी० बी० एस० ई० के बच्चों के नम्बर मिलते हैं, जिसकी बिना पर हरियाणा के बच्चे ऐडमिशन से वंचित रह जाते हैं। कई जगहों पर ऐसा हुआ भी है। दिल्ली में ऐसा हुआ है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने जा रही है जिससे कि हरियाणा के बच्चों को इंजीनियरिंग कालेजिज में ऐडमिशन मिल सके और उन्हें मार्कस भी अच्छे मिले?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर सर, हम सी० बी० एस० ई० का सिलेबस अख्तियार कर रहे हैं और मार्किंग के हिसाब से भी इन सभी बातों का ध्यान में रखा जाएगा ताकि हरियाणा के स्कूलों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव न होने पाए। इस साल जो

प्रेक्टिकल हुआ है, उसका रिजल्ट खराब रहा है। ऐसा स्टुडेंट्स और टीचर्स दोनों के कारण हुआ है। हमें आता है कि जब हम सी० बी० एस० ई० का सिलेबस अख्तियार कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा और उसी के हिसाब से हरियाणा के बच्चों को भी इंजीनियरिंग कालेजिज में एडमिशन मिल पाएगा।

श्री हजार चन्द: स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक स्कूलज और मॉडल स्कूलज हैं, उनमें टीचर्स को वेत दिये थोड़े जाते हैं और कागजों पर ज्यादा लिखाये जाते हैं। क्या सरकार टीचर्स के साथ इस तरह के भाषण को रोकने का प्रबन्ध करेगी?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, ऐसे मामलों में हमें टीचर्स की कोआपरेशन की आवश्यकता है। वे हमें ऐफीडेविट दें, बयान दें। जो रिपोर्ट करते इस सम्बन्ध में हमारे पास आएंगी, हम उन पर सख्ती से कार्यवाही करेंगे और ऐक्टिव लेगे। दूसरा हमें ऐसे मामले में पुलिस का भी कोआपरेशन मिल सकता है। इन चीजों की देखते हुए अगर किसी मैम्बर साहेबान के ध्यान में कोई ऐसी बात हो तो वे हमारे नोटिस में लाएँ अगर इस बार में कोई ऐपीलेंट्स हमारे पास आएगा तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे और सुधार लाने की कोशिश करेंगे।

श्री शिव प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये काफी पग उठाये हैं और

नकल के केसिज में काफी सख्ती बरती गई है। और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के हैड्ज के खिलाफ कोई ऐक्टान लेने का विचार रखती है जहां कारिजल्ट जीरो परसैन्ट आया है?

श्री खुरशीद अहमद: यह आसपैक्ट जेरे गौर है। इस कार्यवाही की जाएगी।

श्री कांति प्रकाश भल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा के स्कूलज में टीचर्ज की बहुत कमी है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई वगैरह ठीक ढंग से नहीं हो पारही है। और बच्चे अमूमन इसी कारण से फेल हो रहे हैं। क्या सरकार इस कमी को जल्दी ही पूरा करने का विचार रखती हैं अगर सरकार का ऐसा विचार है तो कब तक सभी स्कूलज में टीचर्ज की कमी को पूरा कर दिया जाएगा।

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, टीचर्ज की कमी हर साल बढ़ती चली जा रही है क्योंकि स्टुडैन्ट्स भी हर साल ज्यादा होते चले जा रहे हैं। हम कोर्ग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा किया जा सके।

श्री कांति प्रकाश भल्ला: स्पीकर साहब, इस समय टीचर्ज की कितनी कमी है? आनरेबल मिनिस्टर यह सूचना इस हाउस में दें।

श्री खुरशीद अहमद: यह सूचना अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके लिये यदि आनरेबल मैम्बर अलग से नोटिस दे, तो हम बता देंगे।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या हथीन क्षेत्र में नूंह और फिरोजपुर झिरका की तरह मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड की तरफ से मॉडल स्कूल खोलने का विचार है? उस बोर्ड के पास पहले ही बहुत पैसा है और मेरा हथीन क्षेत्र भी उसी में पड़ता है?

श्री खुरशीद अहमद: अभी कोई विचार नहीं है।

Veterinary Hospital in Rai Constituency

***608 Sh. Maha Singh:** Will the Minister of state for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Veterinary Hospitals in Rai Constituency in district Sonapat; and

(b) If so, the time by which the aforesaid hospital are likely to be opened together with the criteria, if any, adopted by the Government for setting up Veterinary Hospitals in the State?

पुपालन राज्य मंत्री (श्री अजमत खां):

(क) नहीं

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक नेय हस्पताल खोने के आधार का सम्बन्ध है, सरकार सीधे ही प ु हस्पताल नहीं खोलती है। केवल वर्तमान प ुधन केन्द्र/प ु औशधालय को स्थानीय आव यकताओं को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया जाता है।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय की 'न' के लिए तो मैं धन्यवार ही कर सकता हूं, इसके अलावा और क्या कह सकता हूं? लेकिन मंत्री जी ने यह जो लिखित जवाब के पार्ट (बी) में लिखा है—

“Only the existing stockmen centres/dispensaries are upgraded as Veternary Hospital depending upon the locka requirments.”

इस बारे में मैं कहूंगा कि हल्का राई की बहुत बड़ी लोकल रिक्वायरमेंट है? क्या मंत्री जी वहां पर किसी सेंटर को अपग्रेड करने की कोिा करेगे या यह बताने का कश्ट करेगे कि क्या कोई वैटनरी हस्पताल पूरी राई कांस्टीच्सएंसी में है?

श्री अजमत खां: स्पीकर साहब, मैं डां0 साहब को बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी उसे बाद हमने इनके हल्के में एक तो नई डिस्पैस्री खोली ओर एक को बड़ा किया। ऐसा हमने जाड़ डोशी और अटरेना में किया है जो राई हल्के में ही हैं।

कामरोड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा के अन्दर कुछ हस्पताल ऐसे हैं जिनके अन्दर डाक्टरों की अप्वायंटमेंट नहीं होती और हस्पताल ऐसे ही चलते रहते हैं। जैसे मेरे हल्के का एक गांव है.....

श्री अध्यक्ष: यह सवाल तो राई से संबंध रखता है।

कामरेड़ हरपाल सिंह: एक तरफ तो बेरोजगार डाक्टर फिरते हैं और दूसरी तरफ डिसपैसरीज इनके बगैर खाली पड़ी है। क्या मंत्री जी इनके अन्दर डाक्टरों की अप्वायंटमेंट करेगे?

श्री अजमत खा: यह सवाल राई हल्के में हस्पताल खोने का था इसलिए इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

Upgradation of Schools

***625 Dr. Brij Mohan:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Primary Schools to Middle Schools and from Middle Schools to High Schools in the State during the year 1988-89; if so, the constituency-wise details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य में 50 प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों तथा 25 मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में स्तरोन्नत किए जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचारधीन है। प्रस्ताव का अन्तिम अनुमोदन होने

के अभाव में विधान सभा क्षेत्रवाद स्कूलों की कोई सूची तैयार नहीं की जा सकती।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, मैं आकपे द्वारा मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ इन्होंने कहा कि 50 प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में ओर 25 मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड करने की मामला सरकार के विचारधनी हैं क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह कब तक फाइनेलाइज हो जाएगा? कोई अन्तिम महीना बताएंगे?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, हम इसे बहुत जदल फाइनेलाइज करने की सोच रहे हैं।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन स्कूलों को अपग्रेड करने का क्राइटेरिया क्या है? सिरसा जिला में सब से कम स्कूल है, क्या इसकमी को पूरा करने को लिए कोई स्टेप उठा रहे हैं?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, सिरसा में सब से कम ऐलनाबाद के इलाके में स्कूल है। जब हम स्कूलों को अपग्रेड करते हैं तो ऐसे इलाकों का ध्यान रखा जाता है। जो इलाका ज्यादा बैकवर्ड होता है उसे सबसे पहले नम्बर दिया जाता है।

श्री जय नारायण खुंडिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिलावार प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करने की कितनी कितनी संख्या है?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, जब डिस्ट्रिक्टवाइज और कांस्टीच्यूएंसीवाइज लिस्ट बनाई जाएगी, उस समय क्वांटिटी के हिसाब से अगर हर हल्के में एक स्कूल अपग्रेड करने के लिए मिल जाता है तो उस हिसाब से स्कूल अपग्रेड करेंगे। जिसहल्के में स्कूलों की ज्यादा जरूरत है, वहां पर थोड़े ज्यादा स्कूल अपग्रेड करने को बारें में विचार करेंगे और जिस हल्के में पहले ही काफी स्कूल है, वहां पर स्कूलों को अपग्रेड करवाने के लिए मैम्बर साहेबान को थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा।

श्री कैला । चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्कूल अपग्रेड करने के लिए जि समय डिस्ट्रिक्टवाइज ओर कांस्टीच्यूएंसी वाइज लिस्ट बनाई जाएगी, क्या उस समय नांगल चौधरी ओर नारनौल हल्के का विशेष ध्यान रखा जाएगा क्योंकि ये इलाके शिक्षा के हिसाब से बहुत ही पिछड़े हुए हैं और इन इलाकों में अब तक शिक्षा की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, जिस इलाके में शिक्षा की तरफ अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, उस इलाके में शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा।

श्री भागमल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे, क्या उसी तरह से

टैन-प्लस-टू-स्कूलों को भी अपग्रेड करने के बारे में गौर किया जाएगा?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, इसके लिए भी गौर किया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, पिछले दिनों सरकार की नीति सुनने में आई थी कि लड़कियों के स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या लड़कियों के स्कूल इन 50 और 25 स्कूलों के अलावा अपग्रेड किए जाएंगे?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने सरकार की जिस नीति के बारे में सुना है वह लड़कियों के लिए नए प्राइमरी स्कूल खोलने के बारे में थी लड़के-लड़कियों के लिए अलग से ऐक्सकल्यूसिवली स्कूल नहीं होते। स्कूल अपग्रेड करते वक्त लड़के लड़कियों के स्कूल एक साथ मिला कर ही अपग्रेड किए जाते हैं। हैं लेकिन लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए प्रैफरेंस दी जाती है।

श्री रतन लाला कटारिया: स्पीकरसाहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली बार स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जो आधार बनाया गया था, क्या इन 50 और 25 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए उसी आधार को माना जाएगा? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उस समय से

लेकर अब तक बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, क्या ये 50 और 25 स्कूल अपग्रेड होने के बाद उस बढ़ी हुई बच्चों की संख्या को कवर कर सकेंगे?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर सहब, बच्चों की संख्या तो हर साल हम सब की कोटि में के बावजूद भी बढ़ती रहती है। स्टेट के रिसोर्सिज को देखकर हमें जितना पैसा मिलता है, उस हिसाब से हमें स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए लिमिट तय करनी पड़ती है ताकि स्टेट के फाइनेंसिज को ध्यान में रखते हुए उतने पैसे में हम काम कर सकें। इस फाईव ईयर प्लान में स्कूल अपग्रेड करने का जो हमारा कोटा था, वह पूरा कर दिया गया है। इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए ऐक्सट्रा कोटा मांगा गया है। अगर हमें रिसोर्सिज अवेलेबल हो जाएं, तो हम मैम्बर्ज की वह ख्वाई भी पूरी करेंगे ताकि जिनके हल्कों में स्कूलों की ज्यादा कमी है, वह पूरी होसके।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, बजट सेशन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह ऐलान कियाथा कि जिस गांव के लोग लड़कियों के स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाएंगे, उसे लिए सरकार की तरफ से दुगनी मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर किसी गांव के लोग लड़कियों के स्कूल के लिए बिल्डिंग बना कर दें, तो क्या वहां स्कूल भुरु कर दिया जाएगा?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, बिल्कुल भारु कर दिया जाएगा।

कुमारी मेधावी कीति: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने कहा था कि जो हल्के िाक्षा के हिसाब से पिछड़े हुए हैं, उनकी तरफ वि ेश ध्यान दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं। कि झज्जर हल्का िाक्षा के हिसाब से बहुत ही पिछड़ा हुआ हैं और उसकों पिछड़ा हुए इलाका भी घोशित किया हुआ हैं इस क्षेत्र की िाक्षा प्रणाली बहुत पिछड़ी हुई है। इस क्षेत्र में स्कूल अपग्रेड करना तो दूर की बात है, उसमें जो बड़े-बड़े गावं है, उनमें ठीक तरह से स्कूल भी स्थापित नहीं हो सके है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या झज्जर के इलाके की िाक्षा प्रणाली ओर स्कूलों की ठीक व्यवसी करने के बारे में सरकार कोई वि ेश ध्यान देगी?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, झज्जर इलाके की िाक्षा के लिए जरूर वि ेश ध्यान दिया जाएगा।

**New Building of operation Theatre Civil Hospital,
Karnal**

***627 Seth Lachhman Dass Bajaj:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) Wheter it is a fact that the operation theatre of Civil Hospital, Karnal has been declared unsafe by the Public Works Departmen;

(b) Whether it is also a fact that the medical instruments used in the said operation theatre have become unserviceable; and

(c) If so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to construct new building of the said operation theater and replace the unserviceable instruments thereof?

स्वास्थ्य एवम् आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) जी हां। दिनांक 18.7.88

(ख) जी नहीं।

(ग) आपने इन थियेटर का भवन मुरम्मत योग्य नहीं है जैसा कि लोग निर्माण विभाग ने बताया है। नए आपने इन थियेटर का निर्माण परम् अग्रता के आधार पर मुख्य वास्तुक हरियाणा की सलाह अनुसार करवाया जाएगा। आपने इन थियेटर के जो मैडीकल इन्स्ट्र्यूमेंट्स नाकारा हो जाते हैं उनको प्रति वर्ष बदल दिया जाता है। और आपने इन थियेटर में हमें ता प्रयोग के लिए योग्य इन्स्ट्र्यूमेंट्स ही प्रयोग में लाये जाते हैं।

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब तक यह आपने इन थियेटर ठीक नहीं हो जाता जब तक कहीं दूसरी जगह पर मरीजों के आपने इन किए जाने का प्रबंध किया जायेगा।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि करनाल हस्पताल के अन्दरन एक पी० पी० सैन्टर है। वहां के सी० एम० ओ० को लिख दिया गया है कि इस पी० पी० सैन्टर में जो आपने उन थियेटर ठीक नहीं हो जाते तब तक पी० पी० सैन्टर के आपने उन थियेटर में ही आपने उन होंगे।

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सोनीपत के मौजूदा सिविल हस्पताल की हालत बहुत खराब है। मैं इन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि वहां पर नए हस्पताल की बिथलडग तैयार हो चुकी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नई बिल्डिंग का कब तक उद्घाटन कर दिया जायेगा?

श्रीमती कमला वर्मा: दिसम्बर, 1988 तक इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर देंगे।

श्री जय नारायण खुंडिया: स्पीकर साहब, यह सवाल तो करनाल के सिविल हस्पताल से संबंधित है लेकिन चूंकि सवाल सिविल हस्पताल से संबंधित है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि रोहतक सिविल हस्पताल की जो ऐक्सरे में गिन काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है, उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा?

श्रीमती कमला वर्मा: रोहतक सिविल हस्पताल के ऐक्सरे प्लांट की एक ट्यूब खराब हो गई है। हम इसे ठीक कराने के लिए इंजीनियर को लिखते रहे हैं लेकिन जब तक वह आ कर

ठीक नहीं कर जाता जब तक इय समस्या बनी रहती है। मुझे इस बात का पता है वहां का ऐक्सरे प्लांट काम नहीं कर रहा है और मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि इसे भीघ ही ठीक कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल करनाल जिले से संबंधित है मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन्हें कभी किसी हरियाणा के सिविल हस्पताल में ऐडमिट होकर इलाज कराने का मौका मिला है? दूसरे क्या इन्होंने यहां के सिविल हस्पतालों की हालत को अच्छी प्रकार से देखने की कोशिश की है क्योंकि यहां के हस्पतालों में न तो दवाइयां लोगों को मिल पा रही है और न ही दूसरी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हे बताना चाहूंगी कि मुझे कईबार ऐडमिट होने का अवसर मिला है। माननीय सदस्य इसबात के लिए चिन्ता न करे। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मंत्री बनने के बाद मैंने 50 के आसपास हस्पतालों का अचानक निरीक्षण किया है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टाफ की वजह से या दवाइयों की वजह से जा इक्यूपमेंट्स की वजह से लोगों को कोई परेशानी न आएँ सीमित वित्तीय साधनों के कारण कुछ कमियां हैं, जिन्हे ठीक करने का प्रयास है।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि हर सै न में हस्पतालों से संबंधित सवाल आते हैं और हर बात कहा जात है कि हम लोगों को पूरी सुविधाएं दे की को ि ा करते हैं। हर सै न में हर मैम्बर मांग करते हैं कि मेरे यहां के हस्पताल को 50 बैड्ज का कर दिया जाये और जो 150 बैड्ज का है उसे 200 बैड्ज कर दिया जाये। मैं मंत्री जी के उस हस्पताल की हालत देखी थी कि वहां के कमरे टूटे हुए हैं और एक टूटे हुए कमरे में गो खड़े थे। क्या मंत्री जी ने उन खड़े हुए गधों को देखा था? (हंसी) दूसरे क्या वहां पर नया हस्पताल बनाया जायेगा?

श्रीमती कमला वर्मा: मैंने माननीय सदस्य को कई बार कहा है कि आप हमें वहां पर जमीन दिलवा दें, हम बिल्डिंग बना देगो। हमने वहां के लिए स्वीकृति प्राप्त की हुई है। ये जमीन उपलब्ध करवा देगे तो जल्दी ही वहां पर नई बिल्डिंग बना दी जायेगी। जहां तक गधों की बात है, माननीय सदस्य अधिक जानते होंगे, मुझे कोई नहीं दिखा। (हंसी)

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, सिविल अस्पताल, कैथल को 100 से 200 बैड्ज का अस्पताल बने हुए दो साल हो चुक है, वहां पर स्टाफ और म िनरी भी पूरी है लेकिन बिल्डिंग सफि िण्ट नहीं हैं पिछले विधान सभा सै न में भी मैंने यह बात उठाई थी लेकिन मंत्री महोदया ने कोई वि वास नहीं दिलाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से

यह जानना चाहूंगा कि इस अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग को निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?

श्रीमती कमला वर्मा: कैथल में नौर्म के मुताबिक 100 बिस्तर का अस्पताल सैक एन्ड है और निर्धारित नार्म के मुताबिक इस सिविल हस्पताल की बिल्डिंग ठीक है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सवाल पूछने की हमारी हिम्मत नहीं नहोती क्योंकि सवाल करनाल का है लेकिन जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वह फरीदाबाद से संबंधित है। फरीदाबाद में पहले ही एक अस्पताल 'बाद ग़ाह खान' के नाम पर बना हुआ है और इस अस्पताल की हालत के बारे में श्री कुन्दन लाल भाटिया जी ज्यादा बेहतर ऐक्सप्लने कर सकते हैं। फरीदाबाद के सैक्टर 8 में एक बड़ा अस्पताल बनवाने का प्रावधान था। सैक्टर-8 अब पूरी तरह डिवैल्प हो चुका है और इसकी आबादी भी काफी ज्यादा है मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या अब सैक्टर-8 में एक बड़े अस्पताल का निर्माण नीयर फ्यूचर में करवायेगे?

श्रीमती कमला वर्मा: साधन उपलब्ध होने पर इस बारे में अब यही यत्न करेगे।

श्री आत्मा राम गोदारा: अध्यक्ष महोदय, अमूमन देखा गया है कि सिविल अस्पतालों के ऐक्सर-रे प्लांट खरबा ही मिलते हैं। इन ऐक्स-रे प्लांटस को खरबा रखने में वहां के डाक्टरों और

कर्मचारियों की सजिा भी हो सकती है। मै मत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जासकता जिसमें एक स्पैाल स्कवैड बना दिया जाए जो कि इन ऐक्स-रे मीनिनों की निगरानी करें और जो ऐक्स-रे प्लांट खरबा हो, उसे ठीक कर सके?

श्रीमती कमला वर्मा: इस बारे में स्थिति इस प्रकार है कि जिस फर्म से ऐक्सरे प्लांट खरीदा जाता है, उसकी मुरम्मत क लिए वही फर्म रिन्पोन्सिबल होती है। ज्यों ही किसी ऐक्सरे प्लांट के खरबा होने के बारे में हमें सूचना मिलती है, हम तत्काल संबधित फर्म को इन्जीनियम भेजने के लिए लिखते हैं। कई बार फर्म को बार-बार लिखने पर भी इन्जीनियर जल्दी नहीं भेजा जाता। फिर भी हम सूचना मिलने पर ऐक्सरे प्लांट को जल्दी ठीक करवाने का प्रयत्न करते हैं माननीय सदस्य ने 'स्कवैड' बनाने के लिए जो सुझाव दिया है। उसके बारे में भी विचार कर लेगे। हम सोच रहे हैं, अपने ही प्रांत में कुछ तकनीकी लोग तैयार किये जायें।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में डाक्टर तो मिलते हैं, मीनिरी भी मिलती है। लेकिन दिवाई नहीं मिलती। मै स्वास्थ्य मत्री साहिबा से यह जाननता चाहूंगा कि अस्पतालों में दिवाई का पूरा प्रबन्ध कब तक कर दिया जाएगा और दूसरे अस्पताल के अन्य खर्चों और दिवाइयों के खर्च में क्या अनुपात है?

श्रीमती कमला वर्मा: जिस प्रकार से इनडोर और आउटडोर में रोगियों की संख्या बढ़ रही है हम उसी प्रकार से से पे नैन्ट्स को दवाईयां नहीं दे पा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री श्री देवी लाल जी ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके चेयरमैन श्री बी० डी० गुप्ता, उप मुख्य मंत्री जी हैं। यह कमेटी विचार कर रही है कि अस्पतालों में दवाईयां को प्रौविजन किस प्रकार से बढ़ाया जाए। हमने इस कमेटी के माध्यम से कई ऐसे निर्णय लिये हैं जिससे कि अस्पतालों में दवाईयां का प्रावधान अधिक हो सकेगा। बजट के अनुसार विभिन्न अस्पतालों को द जाने वाली दवाईयां का ब्यौरा इस प्रकार है। एक सब-सैन्टर के लिए वर्ष में 2 हजार रूपये की दवाईयां एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर के लिए एक लाख रूपये की दवाईयां और एक अस्पताल के लिए दस से पन्द्रह लाख रूपये की दवाईयां। इस के अतिरिक्त एक सी० एम० ओ० के पास 25 से 35 हजार रूपये की राशि आपात्कालीन स्थिति से निपटने के लिए दी जाती है ताकि किसी ऐक्सीडैन्ट या ऐमरजैन्सी रोगी को दवाई देने में किसी प्रकार की कोताही न हो।

डा० बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, ऐक्सरे मीन रेडियोलोजिस्ट बाहर के प्राइवेट आदमियों से मिली भगत कर लेते हैं और जानबूझ कर अपनी मीन ठीक नहीं होने देते। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है?

श्रीमती कमल वर्मा: आप मुझे लिख कर दें जो दोशी होंगे उनके खिलाफ सख्त ऐक्टान लिया जाएगा।

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी श्री भागी राम जी ने मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यदि वे जमीन उपलब्ध करवा दें, तो वे वहां पर अस्पताल बनवा देंगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह छूट केवल भागी राम जी के लिए ही है या कि सब के लिए है? मैं जितनी जगह ये चाहते देने के लिए तैयार हूं, क्या ये मेरे हल्के में अस्पताल बनवाने की कृपा करेगी।

श्रीमती कमला वर्मा: अस्पताल बनवाने के लिए कुछ नौर्म निर्धारित किये हुए हैं और उन नौर्मज के मुताबिक ही अस्पताल बनाये जा सकते हैं।

Strike in the Cooperative sugar Mill, Shahabad

***588 Sh. Harnam Singh:** Will the Minister of state for cooperation be pleased to state whether any strike took place in the cooperative sugar Mill, Shahabad during the period from 25-1-1988 to 25-02-199; if so, the reasons thereof togetherwith the action taken in the matter?

सहकारित राज्य मंत्री (डा० रघुवीर सिंह): जी हां। सूचना बतौर अनुबन्ध 'क' सदन के पटल पर रखी जाती हैं

अनुबन्ध 'क'

सहकारी चीनी मिल भाहबाद में दिनांक 25.01.1988 को प्रांत: 10-30 बजे से सायं 4-30 बजे तक हड़ताल हुई थी। 21.1.88 को मजदूर संघ ने 4.2.88 को हड़ताल करने के लिए नोअिस दिया था। क्योंकि गन्ना पिड़ाई का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा था, मिल तथा गन्ना उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक निर्देाक द्वारा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को 25.01.1988 को बुलाया गया कि वे हड़ताल ने करे। बातचीत के दौरान श्री बाबूराम, महा सचिव, मजदूर संघ ने प्रबन्धक निदेाक तथा सुरक्षा अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया तथा अभर्द भाशा का प्रयोग किया। उस समय श्री श्री बहादुर सिंह, प्रचार सचिव, मजदूर संघ ने सायरन बाज कर हड़ताल का संकेत सभी कर्मचारियों को दे दिया ओर मिल प्रात: 10-30 बजे बन्द हो गई। प्रबन्धकों द्वारा समझाए जाने पर मिल का कार्य उसी दिन छ: घंटे बाद, बाद दोपहार 4-30 बजे भुरु हो गया।

चार मजदूर जिन्होंने अन्य मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाया था, उन्हें निलम्बित कर दिया गया तथा इस बारे में जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मिल की स्थापना कमेटी की आगामी बैठक में इस बारे में कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो इन्क्वारियों भुरु की गई उनमें अफसरों को कितनी बार बदला जा युका है और कितने

आदमियों से करायी गई है? यह इन्क्वायरी पहले एस० डी० एम० को दी गई, फिर दूसरी बार ए० डी० सी० को दी गई और फिर तीसरी बार डी० सी० को दी गई। इसलिए मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि किस के कहने से ये इन्क्वायरी बदली गई?

डा० रघुबीर सिंह: भाहबाद मिल की कई इन्क्वारियों चल रही है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वे किस इन्क्वायरी की बात कर रहे हैं?

श्री हरनाम सिंह: एक तो लेबरर्ज की भाहबाद भूगर मिल में हड़ताल हुई और दूसरे भाहबाद भूगर मिल के एम० डी० ने जो घपला किया था, उनकी इन्क्वायरी चल रही थी, उनका क्या हुआ?

डा० रघुबीर सिंह: माननीय सदस्य ने दो इन्क्वायरीज का जिक्र किया है। जहां तक मजदूरों की स्ट्राइक का सम्बन्ध है, उसे बारें में हमने ऐक्शन लिया था। जो मजदूर इन्वैल्वड थे, उन्ही के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है। चार वर्कर्स को सस्पैन्ड किया गया था अब उनकी इन्क्वायरी कम्प्लीट हो चुकी है और नैक्सअ मीटिंग एस्टेबलिमेंट कमेटी की होनी है, उस मीटिंग में फैसला लिया जायेगा। जहां तक एम० डी० के विरुद्ध कम्प्लेन्ट की बात है, उसकी इन्क्वायरी ए० डी० सी० कुरुक्षेत्र के पास पैडिंग है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद, उसी के हिसाब से ऐक्शन लिया जायेगा।

कामरेड हरपाल सिंह: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो मजदूर हड़ताल करते हैं, चाहे वे सरकारी मिलों के हैं या दूसरे कारखानों के मजदूर हैं, जब उन्हें पन्निमेंट देने की बात आती है तो दो महीने में दे दी जाती है और जगर मुनाफे की बात आती है या इन्साफ देने की बात आती है डेढ़ डेड साल लग जाता है, इसका क्या कारण है? डेढ़ दो साल तक केस वापिस आता ही नहीं है। मैं आपके द्वारा एक ऐग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कल यहां हाउस में श्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला हम मानने के लिए बाध होते हैं। कई फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मजदूरों के हक में हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें एम्पलीमेंट नहीं करती। जहां तक मजदूरों की सुरक्षा का सवाल है, उस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल करें।

कामरेड हरपाल सिंह: मेरे माननीय साथी ने लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित सवाल उठाया है जो मजदूरों को आप्रेटिव भूगर मिल में लेग हुए हैं, उने बारें में इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वे भूगर मिल में मजदूर के रूप में भी काम करते हैं और भोयर होल्डर भी हैं। किसान के साथ साथ वे मालिक भी हैं। यह किसानों की इन्स्टीच्यूशन है। जहां तक हाईकोर्ट के फैसले की बात है, उस बारें में इस महान सदन की जानकारी के लिए बाना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल

की रहनुमाई में चलती हुई सरकार मजदूरों के हितों के प्रोग्राम लागू करने में सब से आगे है। मेरे साथी कम्यूनिस्ट पार्टी के होने के कारण मजदूरों के बहुत हामी है, लेकिन चौधरी देवी ला की सरकार किसी भी तरह से मजदूरों के हित में सिरी से पीछे नहीं हैं मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे उन मजदूरों को भी श्रेय जाता है और साथ ही अफसरों को भी जाता है कि इतने सूखे के बावजूद भी हमारे महान नेता ने भूगरकेन का भाव 24 रूपये क्विंटल से बढ़ाकर 32 रूपये क्विंटल किया। दूसरी बात यह है कि मजदूरों के कारण आज अकेली भाहबाद भूगर मिल जो अभी तक घाटे में चल रही थी फायदे में ही नहीं आयी बल्कि उसने 1.60 करोड़ रूपये का फायदा किया है।

श्री हरनाम सिंह: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि भाहबाद कोआप्रेटिव भूगर मिल में जो मजदूर तीन-तीन साल से ऐडहौक बेसिज परकाम कर रहे हैं, अब उनको पक्का करने के लिये उन लोगों से दरखास्तें ली जा रही हैं, क्या आपकी यह बात लेबर लाज के खिलाफ नहीं है?

डा० रघुवीर सिंह: मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक भाहबाद कोआप्रेटिव भूगर मिल की बात है, वहां पर सीजन के हिसाब से लोग घटते बढ़ते रहते हैं। आज काम ज्यादा हुआ तो आदमी ज्यादा लग गये और काम कम हुआ तो कम रह गये। मेरा कहने का मतलब यह है कि मजदूर उसी हिसाब से रखे जाते हैं जाह तक उनकी परमानेंट

करने की बात है, हमारे पास जो परमानेंट वर्कर्स हैं, वह थोड़े होते हैं, जो बारह मास काम करते हैं और जिनकी ऑफ सीजन में जरूरत होती है। इनके अलावा हमारे पास कुछ सीजनल ओर कुछ डेली वेजिज पर वर्कर्स होते हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यज जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल के मुख्य कारण क्या थे?

डा० रघुवीर सिंह: स्पीकर सर, वैसे तो मैंने यह इन्फॉर्मेशन इन सदन के पटल पर रख दी है। अगर मेरे माननीय साथी उसको पढ़ते और देखते तो उसके मुख्य कारण पता जाते लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि यह स्ट्राइक जो भी, यह बगैर नोऑस के ही गयी थी। 21 तारीख को एक हड़ताल का नोटिस दिया गया था कि 4 तारीख से हड़ताल पर जायेगे। उस 4 तारीख की हड़ताल को टालने के लिए एक मीटिंग एम० डी० भूगर मिल ने वर्कर्स के साथ की थी। उसमें वर्कर्स को समझाने की कोशिश की गयी। वह वहां पर ऐजीटेड हो गये। उन्होंने एबरप्टली सायरन बजा दिया और मजदूर हड़ताल पर चले गये। वह हड़ताल 6 घंटे तक रही। उसे बाद मजदूर ने जब अपनी गलतियों मानी वह हड़ताल खुल गई।

श्री हरनाम सिंह: इसमें यह कहा गया है कि इन्क्वायरी कर रहे हैं और अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसका

फैसला आने से पहले मिनिस्टर साहब ने जो कह दिया है, यह दरुस्त बात नहीं है।

डा० रघुवीर सिंह: कौन—सी बात के बारें में कह रहे हो?

श्री हरनाम सिंह: आपने अभी कहा कि उन लोगों को इन्साइट किया गया स्पीकर साहब, अभी तक उसकी इन्कवायरी पर ऐक्शन होना पैडिंग है। अभी उस आत का फैसला नहीं आया है लेकिन मिनिस्टर साहब यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं।

डा० रघुवीर सिंह: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि उस दिन की हड़ताल के बाद तो वह लोग अपनी गलती मान कर चले गये। लेकिन आल इंडिया बैसिज पर जो स्ट्राइक 28 तारीख को अखबर में घोषित हुई थी, उससे पहले 27 तारीख को जिस ढंग से उन लोगों ने बर्ताव किया, उस बिना पर 4 आदमी सस्पैन्डिड हैं उनकी इन्कवायरी पर ऐक्शन पैडिंग है। पहली स्ट्राइक के बारें में कोई इन्कवायरी पैडिंग नहीं है।

Construction of Drain

***641 Ch. Kishan Singh Sangwan:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of The Government to construct a drain from village Rithal (Gohana) to Village Kaloi (Rohtak); and

(b) If so, the time by which it is likely to be constructed?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां, एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में जांचधीन है।

(ख) इस स्टेज पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

चौधरी किान सिंह सांगवान: मंत्री महोदय ने बताया है that proposal in this regard is under investigation स्पीकर साहब, रिठाल गांव 1960 से लेकर 1988 तक, सिर्फ दो साल को छोड़कर जबकि सूखा पड़ा था, लगातार 26 साल बाढ़ में डूबा रहा है और यहां के लोग बर्बाद होत रहे है। क्या मंत्री महोदय प्रायरिटी बेसिज पर इस ड्रेन को बनवाने का कश्ट करेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं 27 तारीख को गोहाना जा रहा हूं और चौधरी किान सिंह भी साथ होंगे। उसी दिन डिपार्टमेंट के लोग भी वहां होंगे। जिस प्रकार ऐगजामिने ान चल रहा है उससे इसका कोई न कोई तरीका निकला जाएगा जिससे कि रिठाल गांव के लोगों को कम से कम तकलीफ हो।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर सवाल पूछने से ही मंत्री जी जाने के लिए तैयार हो जाते है तो क्या मंत्री जी मेरे हल्के में भी चलेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब ये हुक्म करेगे, तभी चल पड़ूंगा।

श्री मोहिन्द्र: स्पीकर साहब, उत्तर में दिया है कि प्रोपोजल जांचधीन है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सोनीपत जिले में रोहट कांस्टीचुएँसी में भी कोई मार्डनर बनाना अन्डर कंसीड्रे ान है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेन क्वे चन तो ड्रेन के बारें में है। इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

M.I.T.C. Water Courses Area

***650 Ch. Mahender Partap Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total length in kilometers of water coursed of M.I.T.C lined during the period from July, 1987 in the state?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): 735 किलोमीअर।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैने अपना सवाल कई पार्ट में भेजा था लेकिन उसको काट दिया गया है

श्री अध्यक्ष: यह गलत था।

श्री वीरेन्द्र सिंह: विधान सभा से जो सवाल गया था, उसी का जवाब मैने दिया है। जो चीज गलत होती है उसको विधान सभा सचिवालय काट देता है

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: आपको तो अब सारी चीजे हमारी गलत ही लगती है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: क्या मंत्री महोदय 1972 से अब तक वर्षवार ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे कि एम0 आई0 टी0 सी0 द्वारा कितने किलोमीटर वाटर कोसिज पक्के किए गए और कुल कितना एरिया था?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं 1973-74 से ब्यौरा बता रहा हूँ— 1973-74 में 37 किलोमीअर, 1974-75 में 666 किलोमीटर, 1975-76 में 828 किलोमीअर, 1976-77 में 1215 किलोमीअर, 1977-78 में 536 किलोमीटर, 1978-79 में 809 किलोमीटर, 1979-80 में 2038, 1980-81 में 1769 किलोमीअर, 1981-82 में 1985 किलोमीअर, 1982-83 में 984 किलोमीअर, 1983-84 में 1123 किलोमीअर, 1984-85 में 1575 किलोमीटर, 1985-86 में 1398 किलोमीअर, 1986-87 में 1293 किलोमीअर, 1987-88 में 993 किलोमीटर और अब मैंने बताया है कि 735 किलोमीट बनाये है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एम0 आई0 टी0 सी0 का कितना एरिया ऐसा बाकी है जो अभी पक्का किया जाना है? पिछली सरकार ने फ़ैसला लिया था कि खालों को पक्का करने का पैसा किसानों से नहीं लिया

जाएगा। स्पीकर साहब, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि उस फ़ैसले के मुताबिक 735 किलोमीटर का खर्चा तो किसानों से चार्ज नहीं किया जाएगा?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

अतारांकित प्र न एव उत्तर

Upgradation of Senior Secondary Schools

85 Sh. Raghu Yadav: Will the Minister for education be pleased to state-

(a) The District wise total number of Senior Secondary Schools in the state at present;

(b) The total number of such schools[as referred to in part (a) above, which were upgraded to senior Higher Secondary Schools during the last five years; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools, as referred to in part (a) above, during the year 1988-89 together with the number thereof in district Mohindergarh?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क) राज्य में सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की कुल संख्या का जिलावार विवरण अनुबन्ध 'क' पर रखा है।

(ख) सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अपग्रेड नहीं किया जाता। इसलिए प्र न के इस भाग का उत्तर देने का प्र न ही नहीं उठता।

(ग) सीनियर सैकण्डरी स्कूलों जिनका जिकर ऊपर भाग (क) में किया गया है को अपग्रेड करने का प्र न ही नहीं उठता क्योंकि सीनियर सैकण्डरी स्कूल राज्य में स्कूल शिक्षा की अन्तिम स्टेज हैं

अनुबन्ध 'क'

राज्य में इस समय जिलावार कुल राजकीय/अराजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या ।

जिला का नाम	राजकीय	अराजकीय	कुल योग
अम्बाला	11	11	22
भिवानी	13	4	17
जींद	9	4	13
फरीदाबाद	11	4	15
गुडगांव	10	2	12
हिसार	17	2	19

करनाल	13	4	17
कुरुक्षेत्र	6	5	11
महेन्द्रगढ़	11		11
रोहतक	17	2	19
सोनीपत	7	7	14
सिरसा	8	2	10
कुल योग	133	47	180

(ii) 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली भुरु करने पर वर्षवार स्तरोन्नत किये गये सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की संख्या

वर्ष	राजकीय	अराजकीय
1985-86	132	20
1986-87	1. राजकीय उच्च विद्यालय को स्तरोन्नत किया गया जिसे भौक्षिक सत्र 1987-88 से विद्यार्थियों को प्रवेा देने की	7

	अनुमति दी गई	
1987-88		10
1988-89		10
कुल योग	133	47

**Repair Construction of School buidling in the
state**

86. Sh. Raghu Yadav: Will the Minister for education be pleased to state-

(a) The total amount sanctioned and spend on the construction and repairing of school buidling during the year 1985-86 (up date), and Rewari Constituency, separately;

(b) The total amount, out of that, as referred to in part (a) above sanctioned for District Mohindergarh and Rewari Constituency, separately; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of Government to ochange the procedure of the sanctioning/spending of building fund of the school?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरीद अहमद):

(क) विद्यालय भवनों के निर्माण/मुरम्मत हेतु स्वीकृत राशि तथा खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय
1985-86	328.37	305.59
1986-87	540.46	498.80
1987-88	385.50	374.13
1988-89	372.00	उपलब्ध नहीं

(ख) जिलावार राशि स्वीकृतियां जारी नहीं की जाती।

(ग) हां जी, मामला विचारधीन है।

Supply of stationery Articles to schools

87. Sh. Raghu Yadav: Will the Minister for education be pleased to state-

(a) The total number of manufactures who were allotted the work of supply exercise books for schools in the state during the years 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 and 1988-89 (up date) togetherwith the quantity thereof allotted and supplied by them; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government Consumer stores for the supply of stationery articles, science appartus and sports goods etc. to the schools?

Interim Reply

“D.O. No.....”

Minister of state for
Cooperation, Haryana.

Dr. Raghuvir Singh

M.Sc., LL.B., Ph.D

Subject: Unstarred question No. 87 listed for 24-08-1988.

Dear Chatha Sahab,

The above cited question was transferred to my department by the education department only yesterday. On study of the question, I find that the information will have to be collected from all over the state, which will take at least a month. It is, therefore, requested that a month's extension may kindly be granted for supplying information to the Vidhan Sabha.

With Regards.

Your Sincerely,

Sd/-

(Raghuvir Singh)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Kund Mines

88. Sh Raghu Yadav: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) The time since when the digging work is being done by the Haryana Minerals Ltd. in the mines of Kund;

(b) The number of labourers working therein for more than five years; and

(c) Whether the said labourers are working on permanent basis?

उद्योग मंत्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क) दिसम्बर, 1972 से।

(ख) 196

(ग) नियमित / स्थाई

विभिन्न विशयों को उठाया जाना

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने दो काल अटैन्डान्स में आपका क्या निर्णय है? मेरा पहला मोडर्न मुख्य मंत्री महोदय के टेलीफोन टेप करने से सम्बन्धित था। इस बारे में 32 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से आरोप भी लगाया है।

श्री अध्यक्ष: यादव याहब, इस बारे में सरकार से कमेंट्स मांगे हुए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं।

श्री रघु यादव: मेरा दूसरा मौान वृद्धावस्था पैान के बारें में है। रेवाड़ी क्षेत्र के कई पात्र बुजुर्गों के नाम उस पैान सूची में से काट दिए गये हैं। उसका क्या बना? बड़ा महत्वपूर्ण मसला है

Mr. Speaker: Yadav Ji, that has been dis-allowed.

श्री रघु यादव: स्पीकर साहब, एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 की 20वी रिपोर्ट के बारें में, मैंने रूल 84 के अन्तर्गत डिस्कानका एक नोअिस दिया था। उस का क्या बना?

श्री अध्यक्ष: वह 26.08.1988 के लिए लगाया गया है

श्री रघु यादव: धन्यवाद

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मौान का नोटिस फरीदाबाद कम्पलैक्स के बारें में दिया था उसका या फेट है?

श्री अध्यक्ष: वह 25.08.1988 के लिए लगाया गया है।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, व्यापरियों से सम्बन्धित फार्म 38 के बारें में मेरा एक काल अटैन्शन मौान था उसका क्या फेट है? अगर सम्बन्धित मंत्री महोदय उस बारें में अपने ब्यान दे दे तो हम उनके कृतज्ञ होंगे।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब इसकेलिये सरकार से कमेंट्स मांगे हुए हैं।

कामरोड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा एक प्रिवलिज मोशन था, उस बारें में बता दीजिएगा क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: आपका मोशन विचारधीन है?

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष: आलरेडी काल अटैन्शन नं० 2 ओर 4 उसी सबजेक्ट पर ऐडमिटिड है। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री बलबरी सिंह चौधरी: धन्यवाद जी।

श्री कुन्दर लाल भाटिया: स्पीकरसाहब, 22 तारीख को फरीदाबाद की सफाई के बारें में मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन दिया था उसके बारें में क्या फैसला हुआ?

श्री अध्यक्ष: इस बारें में आपका कोई नोटिस नहीं आया है। आप कृपया बैठिए

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैंने जीरी के भाव से संबंधित एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया कि जीरी आजकल मार्किट में आने वाली है और सरकार ने इसका भाव केवल डेढ़ सौ रूपया पर/क्विंटल ही फिक्स किया है, जोकि बहुत थोड़ा है। उसके बारें में जरा बता दीजिएगा कि क्या किया गया है?

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, कब दिया था?

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आज सुबह।

श्री अध्यक्ष: इतनी जल्दल कैसे आ जायेगा? It must be under process of examination.

ध्यानकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा राज्य में उग्रवादियों की गतिविधियों से लोगों में आतंक होने संबंधी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of Call Attention Motion No. 3 from Sh. Hira Nand Arya, M.L.A. regarding terror amongst the people due to terrorist activeites in Haryana State. I admit it. Sh. Hira Nand Arya, may read his notice and the Minister concerned my make a statement there after.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं इस माहने सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा राज्य में इन दिनों उग्रवादियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। पंचकूला में दिनांक 12.8.1988 को बस में हुए बम विस्फोट की घटना जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा घायल हुए तथा जिला अम्बाला व कुरुक्षेत्र की ताजा घटनाओं से लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया है तथा वे बसों में यात्रा करने व सिनेमा आदि देखने से घबराने लगे हैं। सरकार को भाई चारे के वातावरण को और अधिक बिगड़ने से

रोकने जन-धन की हानि से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से वह सदन को सूचित करें।

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, श्री हीरा नन्द आर्य, एम0 एल0 ए0 ने प्रस्ताव द्वारा कहा है कि हरियाणा प्रांत में इन दिनों उग्रवादियों की गतिविधियों तेजी से बढ़ रही है। माअरखा 12.08.1988 को पंचकूला में बस में हुए बम धमाके की घटना जिसमें कई लोगों की मौत हुई तथा घायल हुए तथा अम्बाला जिला के कुरुक्षेत्र की ताजा घटनाओं से लोगों में डर का वातावरण पैदा हो गया है तथा वे बसों में यात्रा करने ओर सिनेमा वगैरह देखने से घबराने लगे हैं। सरकार को भाई चारे से बचाने के लिये फौरी कार्यवाही करनी चाहिए। तथा वह इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सदन को सूचित करे।

स्पीकर साहब, यह कहना गलत है कि हरियाणा प्रांत में उग्रवाद की गतिविधियों बढ़ रही है। 1.1.1987 से लेकर अब तक कुल 8 मुकद्दमात रजिस्टार हुए हैं माअरखा 7.7.1987 को गांव दरियापुर में उग्रवादियों ने हरियाणा राज्य की दो बसों में 34 बस यात्रियों को मार दिया ओर 21 को घायल कर दिया। एक कार चालक को भी मार दिया गया। 1.1.1988 को अज्ञात आतंकवादियों

ने मास्टर विठ्ठल प्रसाद एम० एल० ए० पर अम्बाला भाहर में हमला किया जिसमें उनका नौकर मारा गया। 9.4.1988 को 5 आतंकवादियों ने डा० हरनाम सिंह एम० एल० ए० और उनके परिवार के मैम्बरान पर भाहबाद में उनके घर में हमला किया जिसमें इनका लड़ार, लड़के की बहु ओर इनके साले का लड़का मारे गए और इस घटना में पांच आदमी घायल हुए हैं। 08.05.1988 को रात लगभग 11.30 बजे पानीपत में आतंकवादियों ने 14 लोगो की हत्या कर दी ओर 25 घायल हुए। 19.06.1988 को दो अज्ञात आतंकवादियों ने कुरुक्षेत्र में रामायण सीरियल देख रहे 16 लोगों को बम धमाके से मार दिया और 29 को घायल कर दिया। 20.06.1988 की रात को चार आतंकवादियाने खुशवंत सिनेमा से बाहर आए लोगों पर गोलिया चलाई जिसमें 6 लोग मौके परमारे गए और 9 घायल हुए। 12.08.1988 को हरियाणा राज्य की बस चण्डीगढ़ से चलने के बाद करीब 5.45 बजे पुराने पंचकूला पहुँची, तो उसमें बम फटा। उसमें तीन लोग मारे गए और 32 घायल हुए। 13.08.1988 को एक बम हरियाणा राज्य की बस में पानीपत में मिला। यह बस भी चण्डीगढ़ बस स्टैण्ड से 12.08.1988 को उसी वक्त चली थी जिव वक्त पंचकूला हादसा—ग्रस्त बस चण्डीगढ़ से चली थी। 14.08.1988 को सूचना मिली कि अमृतसरसे एक ट्रक नाजायज हथियार और गोला बारूछ लेकर दिल्ली जा रहा हैं पुलिस फौरन हरकत में आई। पुलिस ने सरगर्मी से पीछा करके ट्रक को राक लिया। उसमें से एक चाइनीज राइल, दो मैगजीन, 115 कारतूस, 38 बोर का पिस्तौल तथा हैंड गरनेड बराम किए। ये

हथियार दिल्ली में सप्लाई किए जाने थे। इसी प्रकार एक और ट्रक को भीरोका गया। जिसमें एक पिस्तौल तथा भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। हरियाणा पुलिस ने प्रान्त में आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए काबले तारीफ काम किया है। लगभग सभी मुलाजिमों को पता लगा लिया है इनमें जिम्मेदार आतंकवादी या तो मुट्ठभेड में मारे गए है या गिरफ्तार कर लिए गए है। कोई भी आदतमी बाकी नहीं रहा। (थम्पिक) 78 लोगों को आतंकवादियों को पनाह देने के लिए गिरफ्तार किया हुआ है दस आतंकवादी, पांच हरियाणा पुलिस और पांच पंजाब पुलिस द्वारा पुलिस मुट्ठ भेड में मारे गए हैं काबिले तारीफ बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने पंचकूला बम धमाके के जिम्मेदार आतंकवादियों की पहचान कर ली है, मगर उनके नाम बनाता केस के हित में हनी हैं दरियापुर कांड के मामले में हमारी पुलिस ने यहां तक कि अपने जीवन को भयंकर खतरे में डाल कर 10/11.11.87 की रात को तीन खुंखार आतंकवादियों को पंजाब के खतरनाक इलाका मोगा से अचानक हमला करे दबोच लिया। इसी प्रकार 29/30.06.88 की रात को हमारी बहादुर पुलिस ने समाना थाना, जिला पटियाला के गांव मुई सप्पा में पुख्ता खबर मिलने पर रेड किया जिसमें खुंखार उग्रवादी कामीरा सिंह मारा गया और डा0 खुंखारवंत सिंह पुलिस की गोली से घायल हुआ और बच कर निकल गया। हरियाणा पुलिस के एक सब इस्पैक्तर श्री राम प्रकाश ने तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक सिपही श्री दौलत राम ने अपने राज्य व देश की आन व भान की खारि तथा राज्य

की पुलिस की बहादुरी की परम्परा को कायर रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। दो पुलिस मुलाजिम, एक ए० एस० आई० श्री सुखबरी सिंह, हरियाणा पुलिस व एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का जवान जख्मी हुआ। इंसपैक्टर सोरण सिंह, इंसपैक्टर विशान सिंह ने 16.08.1988 को हमारी पुलिस के अब्बल दर्ज की बहादुरी तथा वीरता का पूरा सबूत दिया। खुफिया और पुख्ता पुलिस आधार पर कुरुक्षेत्र की खुंखार आतंकवादियों से गांव नीमवाला थाना पेहवा के पास मुठभेड हुई। यह आतंवादी जनरल आर० एस० दियाल के भाई को मारने के लिएआए थे। पुलिस ने दो आतंकवादियों को मौके परमार डाला जिनसे अंसलाव बारूद बरामद हुआ इनमें से एक का नाम गुरचरण सिंह वल्द अमर सिंह साकिन भाहबाद पाया गया जोकि हरियाणा प्रांत की खुद मुकररी एरिया कमाण्डर था और दूसरे की िनाख्त नही हुई। यह आतंकवादी हरियाणा की ज्यादातर आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेवाद था और डा० हरनाम सिंह एम० एल० ए० तथा उसके परिवार पर कातिलाना हमले में प्रमुख अपराधी था। 14.08.1988 को हमारी पुलिस ने एन० आर० एल० पंजाब गुडज कारपोरे न के दो ट्रकों के अमृतसर से काफी तादाद में आतंकवादियों के लिए गोला बारूद ले जाते हुए पकड़ा। यह हथियार बारूद देहली में बहुत बड़ी तोड़ फोड़ की कार्यवाही के लिए ले जाया जा रहे थे। इस कार्यवाही में पुलिस ने सब से बड़ी चुस्ती और वतन धर्म की काबलियत को सबूत दिया। सरकार पूरी तरह जागरूक है ओर उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए ताकत में में आते ही सरकार

ने ठोस कदम उठाए हैं एक डी० आई० जी०, एक एस० पी० दो डी० एस० पी० और चार कमाण्डर कम्पनी तैयार की गई हैं दो हमारे पुलिस कर्मचारियों की पुलिस विभाग नमें नई असामियों मंजूर की गई । भारत सरकार को मदद के लिए लिखा गया । 50 लाख रूपए की ग्रांट भारत सरकार ने दी जिससे काफी तादाद में गाड़िया खरीदी गई । पांच कम्पनिया बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० और 6 कम्पनियां गुजरात आर्मड पुलिस को इकट्ठा करके तैनात किया गया । राज्य में ग त म तक जगहों की सुरक्षा तथा खुफिया विभाग को मजबूत कर दिया गया हैं रेल तथा बसों के अन्दर असला पुलिस दस्ते भेजे जा रहे हैं । वी० अवई० पीज० की हिफाजत के लिए मुनासिब इन्तजाम किए गए हैं इस सिलसिले में हमारी पुलिस से बहादुरी का एक सबूत यह मिला है कि हमारे अभी काल ही में सिरसा में लोक सभा के लिए चुने गए श्री हेतराम एम० पी० बस में जा रहे थे और किसी ने ड्राइवर के सिर पर पिस्तौल रख करके बस को लिक रोड पर ले जाने के लिए कहा लेकिन हमारी पुलिस इतनी चौकत्री है कि उसको वही पर जखमी कर दिया और गिरफ्तार कर लिया । मैं आपके सामने बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे यहां जितनी भी आतंकवादी वारदाते हुई हैं इनमें या तो इस तरह की वारदात करने वाले मारे गए या हमारी गिरफ्त में हैं । हमारी पुलिस इतनी चौकत्री है कि इस समय हरियाणा में कहीं पर भी भय का नामो-नि गान नहीं है ।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, आरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने हरियाणा प्रदेश में आतंकवादियों की भड़क को रोकने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में बड़े विस्तार से बताया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार से इस विषय में जिस प्रकार की उनसे सहायता मांगी गई थी, क्या उसके अनुरूप सहायता दी गई और दी जा रही है या उसमें कुछ ढील बरती जा रही है? अगर केन्द्रीय सरकार उसमें कुछ ढील बरत रही है तो उसके लिए हमारी सरकार और क्या खतोकिताबत कर रही है?

चौधरी देवी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमारी तरह से पूरी कोशिश की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार से इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद ली जाए। इस बात के लिए केन्द्रीय सरकार पर बार-बार जोर डाला जा रहा है मुझे उम्मीद है कि यदि केन्द्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा में हालात को सुधारना चाहती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मदद देगी।

(ii) राजस्व मंत्री द्वारा हरियाणा में वर्षा तथा बाढ़ से फसल तथा सम्पत्ति को क्षति होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, श्री हीरा नन्द आर्य एम० एल० ए० की कालिग अटैचमेंट नं० 2 और श्री हरनाम सिंह, एम० एल० ए० का कालिग अटैचमेंट नं० 4 (2 के साथ ब्रेकेटिड) जो डैमेज आफ क्रोप्स एंड प्रॉपर्टी इन हरियाणा वाई

रेन्ज एंड बाढ के बारे में थी, प कल रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने आज अपनी स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। वे कृपया अपनी स्टेटमेंट दे।

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष के अपूर्व सूखे के प चात इस वर्ष मौनसून की वर्षा अच्छी हुई है यद्यपि समय पर मौनसून आ जाने का कृशकों द्वारा सारे राज्य में स्वागत किया गया था अपितु भारी वर्षा के कारण मुख्यतः राज्य के 8 जिलां नामतः अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद सिरसा, टांगरी तथा मारकण्डा नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा से इन नदियों को बहाव बढ़ गया। टांगरी बन्ध में तीन स्थानों पर कटाव आने से अम्बाला व कुरुक्षेत्र जिलों के काफी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। इसी प्रकार पंजाब क्षेत्र में घग्गर बांध के कटाव से जिला कुरुक्षेत्र तथा हिसार के बहुत से क्षेत्र बाढ़ आ गई। पंजाब में पच्चीस धारा के किनारों में कटाव के कारण एस० वाई० एल० में बाढ़ का पानी आया, जससे यह नहर 2 स्थानों पर टूटी और अम्बाला व कुरुक्षेत्र जिलों के काफी गांव जलमग्न हो गये। थानेसर भाहर की कुछ आबादी भी प्रभावित हुई। यमुना नदी द्वारा रुख बदलने पर करनाल जिले में पीरबरोली गांव की सारी आबादी बह गई। कुरुक्षेत्र, सोनीपत व फरीदाबाद के जिलों की कुछ आबादी प्रभावित हुई। सूरजपूर के नजदीक राष्ट्रीय जनमार्ग पर झाजरा नदी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ तथा यातायात को चालू रखने हेतू बैली ब्रिज बनाने के लिए सैनिक सहायता प्राप्त की गई। इसी

प्रकार कुरुक्षेत्र जिले में एस0 वाई0 एल0 में आये कटाव को भरने के लिए तथा कुरुक्षेत्र, हिसार व फरीदाबाद जिलों में जल-मग्न क्षेत्रों से व्यक्तियों, उनके पशुओं तथा उनके अन्य सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये भी सैनिक सहायता प्राप्त की गई। बाढ़ के पानी को निकालने तथा कटावों को भरने हेतु प्रभावी पग उठाये गये।

2. प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार लगभग 90000 हैक्टियर फसली क्षेत्र प्रभावित हुए और फसलों को लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि की हानि का अनुमान है। विशेष गिरदारी के आदेश दिये जा चुके हैं और उसके परिणाम प्रतीक्षित हैं जन सेवाएं जैसे सड़के, पुल सिंचाई जन स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि का नुकसान 20.94 करोड़ रुपये हुआ है लगभग 30000 कच्चे व पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं बाढ़ के पानी के नलकूपों को भी नुकसान पहुंचा है जिसका अन्दाजा लगाया जा रहा है।

3. इस वर्षा ऋतु में पीलिये के 367 केस हुए जिनमें से 227 मामले सिरसा जिले में हुए हैं। सिरसा जिले में पीलिया के अधिक केस होने का कारण सिवरजि पाईप लीक होना है जिसके कारण पीने का पानी दूषित हो गयारू। जुलाई, 1988 में मलेरिया के 475 मामले सामने आये। जुलाई 1988 से अब तक हैजा के 52 केस जिन में 2 की मृत्यु हो गई तथा 1634 केस जिन में से 39 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन बीमारियों को रोकने के लिये

आवश्यक उपाये किये गये हैं। पंजाब में किसी बीमारी के उत्पन्न होने की कोई सूचना नहीं है।

4. बाढ़ से प्रभावित समस्याओं से राज्य सरकार भली-भांति जागरूक है। राज्यपाल हरियाणा तथा मुख्य मंत्री हरियाणा ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है तथा विभागीय अधिकारी भी खतरों वाले सभी स्थानों पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिये तुरन्त आवश्यक कदम उठाये हैं और इसी उद्देश्य के लिये 305.75 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	उद्देश्य तथा जिसको राशि स्वीकृत की गई थी	राशि (रु० लाखों में)
1.	सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, आश्रय देने, खाना, चारा तथा रिग बन्ध को मैनटेन करने के लिए उपायुक्तों को	79.40
2.	जल निकासी, किनारों तथा ड्रेनेज की मरम्मत एवं पुनः चालू करने के लिये सिंचाई विभाग को	95.00
3.	पम्प सैट, भाहरों में जल निकासी तथा पीने के पानी के लिये हैंड पम्पों के लिये जन	36.00

	स्वास्थ्य विभाग को	
4.	सड़कों की मुरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के भाखा) को	90.00
5.	स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाओं के लिये	5.00
	कुल जोड़	305.75

बाढ़ तथा भारी वर्षा से जिन 17 व्यक्तियों की मृत्यु बाद के पानी में डूबने तथा मकानों के गिरने के कारण हुई है, के नजदीकी रिश्तेदारों को मुख्य मंत्री सहायता कोश से 10000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दिये गये हैं बाढ़ के दौरान 62 पशुओं की मृत्यु भी हुई है।

बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये 16 सहायता कैंम्पस तथा 74 स्वास्थ्य कैंम्पस लगाये गये हैं तथा जल-मग्न क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है कैंम्पों में रह रहे व्यक्तियों को बना हुआ खाना तथा अन्य प्रभावित जनसंख्या को सस्ते दर पर राशन तथा पशुओं के लिये मुक्त चारा भी उपलब्ध किया गया। अब तक 3188 सिरकीज, 35000 खाली सीमेन्ट बैग, 477 क्विंटल आटा, 13 क्विंटल चने तथा 3.5 क्विंटल दाल बांटी गई। इसके अतिरिक्त 40000 रुपये की अन्य आवश्यक सामग्री भी बांटी गई। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के कार्य प्राथमिकता के आधार पर चालू करने के लिये आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं। बाढ़ ग्रस्त

क्षेत्रों में पुनः फसल बोने हेतु धान की फसल के लिए फासफैटिंग खाद पर 20 प्रति टन छूट दी जायेगी। कृषकों को अगली रबी फसल बोने हेतु काफी इनपुट सबसिडी दी जायेगी। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों व गर्भवती तथा दूध पिलानी वाली माताओं के लिये अनुपूरक पौष्टिक आहार भी प्रदान किया जायेगा। मनु यों तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के रोकथाम के उपाये जारी रहेगे। कृषक समाज के दुखों को दूर करने के लिये अल्प अवधि वाले सहाकारी ऋणों को लघु अवधि ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि बाढ़ से जो नलकूप खराब हो जायेगे उनसे बिजली का खर्चा उस अवधि के लिये नहीं लिया जायेगा जिस अवधि के दौरान ये नलकूप कार्य नहीं करेगे।

इसलिए केन्द्रीय सरकार को 20.00 करोड़ रुपये की तदर्थ केन्द्रीय सहायता तुरन्तत प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया है तथा 82.13 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान का विवरण भी भारत सरकार को दिनांक 17.08.1988 को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक विस्तृत ज्ञापन भारत सरकार को भीघ ही प्रस्तुत किया जायेगा।

मैं इस अवसर पर सदन का विवास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित जनता की कठिनाईयों को दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ से प्रभावित लोगों की परेशानियों को मिटाने के लिये सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके बारे में मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बाढ़ राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार से कितने पैसे का प्रावधान करवा रहे हैं और जो 20 करोड़ रुपये की राशि की मांग केन्द्र सरकार से की गई है उसका क्या आधार है? जहाँ तक मैं समझता हूँ बाढ़ राहत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि बहुत की कम आंकी है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार ने उसका कोई जवाब दिया है या कि नहीं, यदि नहीं तो इसके लिए हमारी सरकार क्या पग उठा रही है?

श्री सूरज भान: इस बारे में हमने चार तारीख को केन्द्र सरकारको एक टेलीग्राम दिया है इसके साथ ही साथ स्पैल गिरदावरी के आदेश भी दिए गए हैं। गिरदावरी के बादही नुकसान का पता चल सकेगा। जहाँ तक 20 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र से मांगने का सम्बन्ध है, यह राशि तदर्थ तौर पर मांगी गई है। और गिरदावरी के बाद ही केन्द्रीय सरकार से वाञ्छित राशि की मांग की जा सकेगी।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में जब भी बाढ़ आती है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। बरसात से पहले इन जिलों में वाटर लेवल 50—50 ओर 60—60 फुट नीचे चला जाता है। जिसके लिए किसानों को

ट्यूबवैलों के लिए कुए बनाने पड़ते हैं यक कुए 50—60 फुट की गहराई तक खोदने पड़ते हैं? जब बाढ़ आती है तो इन कुओं में जहरीली गैस बन जाती है जिसके फलस्वरूप बाढ़ के कारण कुओं जहरीली गैस से अनेकों आदमी इन दोनों जिलों में मर गये है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन जिलों में भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक क्वै चन है, इसका डिटैल रिप्लाइ उस दिन दे देगे।

श्री भाग मल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मारकन्डा नदी के किनारे और रूहन नदी के किनारे हमारे दो तीन गांव है जैसे संगरहनी, मियांपुर और छोटी रसोल उन्हें खाली करने के आदे 1 दड़े दिये गये हैं वहां पर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ रहा है जब हमने डी0 सी0 साहब को अप्रोच किया कि इन गांवों को बचाने के लिये कुछ उपाय किये जाये तो उनहोने जवाब दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या डी0 सी0 अम्बाला को पैसा दे कर उनगांवों को बचाने की कोशिश की जायेगी क्योंकि उन गांवों में लाखों रूपये के मकान बनाये हुए है, अगर वे गिर गये तो दुबारा नहीं बनाये जा सकेगे।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, कल श्री भाग मल जी ने हाउस में जिक्र किया था कि रोहन नदी पवर मियांपुर और

संगरहनी गांवों को खतरा है। मियांपुर गांव में स्टै को काम भुरु हो चुका है, वहां पर काम बाढ के कारण रोका गया था लेकिन अब लगातार चल रहा है। संगरहनी का काम देखने के लिए एस0 डी0 एम0 को आदे ा दे दिये है। मारकण्डा के नीचे दो गांव आते है एक चमेल माजरा और दूसरा छोटा रसोल। जहां तक चमेल माजरे का संबध है वहां पर ऐम्बैकमेंट प्रोजैक्ट सैव ान हो चुकी है। बरसात के बाद काम भु कर दिया जायेगा और छोटी रसोल के बारें में रिपोर्ट मांगी हैं

श्री हरनाम सिंह: मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा बाढ कन्ट्रोल सिस्टम फेल नहीं हुआ। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं। टांगरी बांध टूटा, बीबीपुर झील का बांध तीन बार टूटा है ओर लोगों ने बान्धा है। सरस्वती ड्रेन टूटी हैं और हमारे लेबर मिनिस्टर के गांव के साथ हिसार रोड का बान्ध रहे है। यानी बाढ ने काफी जगहों पर नुकसान किया है। दूसरीबात यह है कि जितना इन्होंने नुकसान बताया है, वह बहुत कम बताया हैं इन्होंने 566 गांवों को नुकसान बताया है जब कि अकेले कुरुक्षेत्र जिले में ऐग्रीकलचर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि 378 गांवों में 75 हजार एकड़ जमीन में जीरी का नुकसान हुआ हैं जो नुकसान आंका गयाहै, यह बहुत कम आंका गया हैं आपको पता ही हैं कि सूरजपुर का हमारा पुल बह गया। इसलिए मेरी गुजारि है कि इस पर बहस होनी चाहिए राहत के कामों का यहां पर जिक्र तक नहीं किया गया है। काम के बदले अनाज की

स्कीम चालू किया जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि यह अन्दाजा है। हमने स्पै रल गिरदावरी के आदे र दिये हुए है, उसके बाद ही ठीक अन्दाजा लगेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मुझे बड़ा खेद है कि मेरी काल टिन् रन मो रन का जवाब नहीं दिया गया। वह बड़ी स्पैसिफिक थी। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप इसके बारे में सप्लीमेंटरी कर सकते है, भाषण नहीं दे सकते।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब मिनिस्टर महोदय ने मेरी काल अटैन्शन मो रन का कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: आपकी काल अटैन् रन मो रन होने के कारण ही आपको सप्लीमेंटरी करने की इजाजत दी गई है

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, जितना बाढ़ मेरे इलाके में आया उतना और कहीं भी हिन्दुस्तान में नहीं आया है। (विधन) सर, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी काल अटैन् रन को आपके आफिस वालों ने पूरा पढ़ा नहीं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: यह बड़ी अनफारच्युनेट बात है। आपको प्रोसीजर का पता ही नहीं है अगर आपको प्रोसीजर का पता होता हाते आप यहां हाउस में यह बात न करते। आप सवाल करें।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्र जी को मालूम है कि कितनी बार घग्गर, टांगरी और मारकण्डा में उफान आया और वह सारा का सारा खनौरी हैड से ही कर हिसार जिले में जाता रहा?

श्री अध्यक्ष: आप सप्लीमेंटरी करें।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस बार कितनी बार बाढ़ आयी और उस बाढ़ का सारा पानी फतेहाबाद के आस-पास 40 गांवों में जो मेरे हल्के में पड़ते हैं, भर गया था और इस वक्त भी 5-6 गांवों में जो रतियां हल्के में हैं, 5 से लेकर 10 फुट तक पानी खड़ा हुआ है।, जबकि हिन्दुस्तान में कहीं पर बाढ़ का पानी नहीं खड़ा है?

श्री अध्यक्ष: यह भाषण है या सवाल है? आप सीधा या सवाल पूछें! (व्यवधान व भाोर)

श्री बलबीर सिंह चौधरी: मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि उसके लिये इन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है मंत्री महोदय इस बात की इन्कवायरी करायेगे कि प्र आसन की

लापरवाही की वजह से क्या इन गांवों में बाढ़ के कारण इतना भारी नुकसान हुआ है? (विधन)

श्री अध्यक्ष: चौधरी बलबीर सिंह जी, अब आप बैठिये।
This is not the way.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: इस बाढ़ से जो लोगों का नुकसान हुआ है, क्या उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी?
(Interruption & Noise)

Mr. Speaker: I won't allow you. Please sit down.
You are not permitted to speak.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, * * *
*

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, मुझे सारी जानकारी है। केवल मुझे जानकारी नहीं नहीं, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी मौके पर जाकर देख आये हैं पानी का पम्प आउट किया जा रहा है।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब एक मिनिस्टर मूव करेगे कि हरियाणा विधानसभा के रूलज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैसके रूल 30 को सस्पेंड किया जाये और थर्सडे 25 अगस्त, 1988 को सरकारी कात किया जाये।

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): Sir, I beg to move-

That rule 30 of the rules of procedure of and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 25th August, 1988.

Mr. Speaker: Motion moved-

कि हरियाणा विधान सभा के रूलज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 30 को सस्पेंड किया जाये और थर्सडे 25 अगस्त, 1988 को सरकारी काम किया जाये।

श्री रधु यादव: स्पीकर साहब, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सामान्य प्रक्रियो के अनुरूप हमें, जो इस महान सदन के सदस्य है, बृहस्पतिवार के दिन अपने गैर सरकारी संकल्प सदन के सम्मुख रखने का अवसर मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे माननीय सदस्य चौधरी रणजीत सिंह का गैर सरकारी संकल्प, जो कन्साईनमेंट टैक्स के बारे में था, सदन के सम्मुख बहस के लिए प्रस्तुत है और एक संकल्प में भी एक साल से यहां पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसका नोटिस दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अभी तक पहला रैजोल्यूशन ही चल रहा है आपका तो चला ही नहीं है।

श्री रघु यादव: हरियाणा प्रांत में रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिये अहीरवाल डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया जाये, मैंने उस बारे में एक गैर-सरकारी संकल्प आपकी सेवा में प्रस्तुत किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जो ऐप्रूव आप कर चुके हो।

श्री रघु यादव: इस मौके पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जे से केवल गुजारि । करना चाहूंगा कि वे कल गैर सरकारी बिजनैस चलने दें और मेरा अहीरवाल डिवैल्पमेंट बोर्ड वाला गैर-सरकारी संकल्प सदन के सामने बहस हेतु आने दे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, यह जो माननीय सदस्य रघु यादव जी बो रहे थे, यह भायद इसबात को भूल गये कि 22 तारीख को बजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी थी। उस दिन भी यह ये एक भाब्भी नहीं बोल। जहां तक इनके प्रस्ताव का ताल्लुक है, यह प्रस्ताव कैसे आयेगा? अभी तो पिछला प्रस्ताव पैडिंग है। नैक्स्ट सै ।न में या अगर इसी सै ।न में अगर कोईअगला वीरवार आया तो उस पर डिस्क ।न जारी रहेगी। जो इन माननीय सदस्य को रैजोल्यू ।न है, वह तो अभी नजदीक और पास भी नहीं है। लजेकिन यह बार-बार उसकी चर्चा करत रहते है। वह तो अभी करीब ही नहीं है पता नहीं उकस नम्बर आये या न आये। अगर

और रैज्योलू इन आ जोय तो फिर उनकी बैलिटिंग होगी। इसलिये उनका जो वह प्वायंट है, यह बैलिड नहीं है।

Mr. Speaker: Question is-

कि हरियाणा विधान सभा के रूलज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 30 को सस्पैड किया जाये और थर्सथे 25 अगस्त, 1988 को सरकारी काम किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष: अब आनरेबल मिनिस्टर टेबल आफ दि हाउस पर पेपर ले करेगें।

Irrigaton & Power Minister (Sh.Verender Singh):

Sir, I lay on the table the Excise and Taxation Department Notification no. G.S.R. 38/H.A. 20/73/S. 64/Amd. (1)/88 dated the 30th April, 1988 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

बिलज

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए इन (नं0 3) बिल, 1988

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए इन (नं0 3) बिल, 1988 को इंट्रोड्यूस करेगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो इन मूव करेगे।

उप-मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (सं० ३) विधेयक, १९८८ को प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ

कि हरियाणा विनियोग (सं० ३) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That schedule be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

उप-मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा मुड कंडक्ट प्रिजनर्ज (टैम्पोरेरी रिलीज)
बिल, 1988

श्री अध्यक्ष: अब स्टेट मिनिस्टर फार सो ल वैलफेयर एण्ड जेलज दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्ज (टैम्पोरेरी रिलीज) बिल, 1988 को इंट्रोड्यूस करेगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो लन मूव करेगे।

Minster of state for Jails (Sh. Nar Singh Dhandu):
Sir I introduce the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill, 1988.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Bill be taken into consideration at once.

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सम्मुख समाज कल्याण तथा जेल मंत्री श्री नर सिंह ढांडा ने अभी एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) यह संशोधन विधेयक आज इस महान सदन के सम्माननीय सदस्यों की जेल की चार दीवारी के भीतर दुनिया में झाकने का मौका देता है। जिसको सामान्य तौर पर देखा नहीं जाता। उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति के मन में कई बार ऐसी भावना उठती है कि जिससे वह अपराध कर सकता है। कुछ लोग उन भावनाओं पर काबू पा लेते हैं और कई बार भवावे में किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में ऐसा काम भी हो जाता है कि जो कानून की दृष्टि में अपराध है और जिसके लिए उसे दण्ड दिया जाना जरूरी हो जाता है ताकि समाज सुचारु रूप से चल सके। जेल के भीतर, चार दीवारी में, उस व्यक्ति को सुधारने का प्रयास होना चाहिए न कि उसके दमन का प्रयास होना चाहिए। यह एक मानव है। एक गलती उसने की है। भविष्य में वह ऐसी गलती न करे, समाज में कोई और उस तरह का व्यवहार और उस तरह की गलती न करें, इसलिए जेल के दण्ड का प्रावधान होता है। खेद की बात है कि आज भी ब्रिटिश काल के दौरान जो जेल मैनुअल बनाया गया था वही सभी जेलों में लागू है। उसी के अन्तर्गत कई व्यक्ति जेल की सलाखों के भीतर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी संघर्ष से गुजरे हुए व्यक्ति हैं और मुझ खुशी है। कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल भल जनता के लिये संघर्ष करते हुए कई बार जेल की दीवारों के भीतर रहे हैं। अज

जो सरकार हरियाणा पर भासन कर रही है, उ सरकार के कर्णधारी में से बहुत से लोग जेल की चार दीवारी के भीतर कुछ समय व्यतीत कर चुके है। यह जो सं गोधन विधेयक इस समय सदन के सम्मुख बहस के लिए प्रस्तुत है, उसका मैं भरपूर स्वागत और समर्थन करता हूँ। साथ ही मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय ये यह निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति अपराध करता है कानून तोड़ता है केवल उसको सजा मिलनी चाहिए। यह नी होना चाहिये कि जुल्म कोई करें और उसकी सजा कोई और भी भुगते। यह न्याय का और एक सभ्य समाज का तकाजा नहीं हैं अगर एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है तो यह जुल्म है और उसको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है उसके बच्चे, पत्नी और बूढ़े मां बाप भी होते है जो उसकी कमाई पर निर्भर हाते है। मैं खुद भी जेल में रहा हूँ। भजन लाल और चौधरी बंसी लाल के भासन के दौरान हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा के लिये, हम रात दिन सड़कों पर आदोलन करत रहे है। उस समय हम पर झूठे मुकदमें बनाये जाते थे और हमें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। 17 जून, 1987 को जो ऐतिहासिक फैसला हरियाणा की जनता ने दिया, उससे कुछ दिन पूर्व ही मैं स्वयं महेन्द्रगढ़ की जेल में 70 दिनों तक बन्द रहा हूँ। मुझ पर यह आरोप था कि मैंने एक तहसीलदार की हत्या के प्रयास की साजिा की थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते है क्योंकि आपने भी संघर्ष किया था कि चौधरी भजन लाल व चौधरी बंसी लाल के राज में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

चलाया था। जब विजीलैन्स के छापे में रिक्त लेते रंगे हाथों पकड़े जानें के बावजूद भी सरकार एक भ्रष्ट तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करने में आनाकानी करने लगी, जब मुख्य मंत्री और उस वक्त के रेवाड़ी से सम्बन्धित मंत्री भ्रष्ट अधिकारी की पनाह देने लगे तब जनता ने मजबूर होकर चेतावनी देने के बाद सरकार का पूरा समय देने के बाद उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की थी। बजाये उस भ्रष्ट अधिकारी को सजा देने के उल्हा हम पर 307 का झूठा और मनघड़ैत केस बना कर हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तब मैंने 70 दिनों का कारावास भोगा था इससे पहले भी स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण के संघर्ष के दौरान, औश्रचौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में चले संघर्ष के दौरान चाहे रास्ता रोकों का सिलसिला रहा अथवा तानाशाह मुख्य मंत्री बंसी लाल को उखाड़ फेंकने का सवाल रीहा हो, हमने उस वक्त भी सलाखों के पीछे का जीवन देखा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कई बाद ऐसे व्यक्ति भी हत्या कर देता है, कई बाद ऐसा व्यक्ति भी जुल्म कर देता है जिसके ऊपर उसे बूढ़े मां बाप, भाई—बहन दर दर की ठोरके खाने के लिये मजबूर हो जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति विशेष हत्यारा हो सकता है, व्यक्ति विशेष अपराधी हो सकता है लेकिन उसके बच्चे, पत्नी व बूढ़े मां बाप भी अपराधी ही हो ऐसा नहीं होता इसलिये मैं जेल मंत्री महोदय से यह गुजारि करूंगा कि जेल में दंड भोग रहे अपराधी जो काम करते हैं, उन्हें उस काम की जो न्यूनतम मजदूरी बनती है, हमें देनी चाहिए। चाहे टाट बनाने का काम हो, चाहे

निवार या कम्बल बनाने का काम हो, जो भी काम सजा भोग रहे कैदियों से, अपराधियों से हम करवाए, उस का पूरा पूरा भुगतान, कम से कम जो न्यूनतम वेतन की दर होती है, उतना अव य करना चाहिये। और यदि कोई कैदी अपनी परिवारिक स्थिति को देख कर ज्यादा काम करना चाहे तो एक सीमा के बाद जो काम के माप का पैमाना है या आठ घंटे के काम की सीमा का पैमाना हो, उस समय के बाद अगर कोई कैदी काम करता है तो उसे भी ओवर टाइम की तरह कुछ ज्यादा पारिश्रमिक दिया जाए। उसमें से एक हिस्सा विशेषता वह कैदी अपनी जेल की कैन्टीन में खर्च कर कसे लेकिन उकस कम से कम दो तिहाई हिस्सा उसकी पत्नी को किले। अगर उसी पत्नी न हो बूढ़े माता पिता मिले। पत्नी ओर बूढ़े माता पिता न हो तो उस परि आश्रित बच्चों को दिया जाए। (विधन) उपाध्यक्ष महोदय अपराधी एक व्यक्ति हो सकता है, सजा उसी व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए, उसे परिवार के सदस्यों को नहीं मिलनी चाहिए। एक बात का जिक्र मैंने कई बार किया है और सरकार ने हर बाल जवाब दिया है कि हम देख रहे हैं, हमने देखा है, हम देखते रहेगे। मैंने वाहनों के दुरुपयोग और धरेलू नौकरों के रूप में छोटे कर्मचारियों के इस्तेमाल के बारे में कहा है सरकारी अधिकारी अपने घरों में धरेलू नौकरों को बेजा इस्तेमाल करते हैं उस बारे में माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम कुछ करते रहे है, हम कर रहे है और हम करते रहेगे। जो जेल के अधीक्षक और उप अधीक्षक होते है वे कैदियों को अपने घरों में धरेलू काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कैदी उनकी

भैंस की सानी लगाते है। है आउसे घर की सफाई और अन्य सारा काम करते है। ये सारे काम नाजायज रूप से उन कैदियों से करवाए जात है। मै माननीय समाज कल्याण मंत्री से अनुरोध करुंगा कि इसको एकदम से रोका जाए। दूसीर बात, मुझे यह कहते हुए भी बडत्री खु ि हो रही है। चौधरी देवी लाल जी जेल में सुवधियों बेहतर बनाने के पक्ष में है वे चहाते ह कि जेलों के कमरों में पंखे हो और टॉयलेट व बाथरूप का ठीक इंतजाम हो। इस बात को चौधरी देवी लाल हमे ा कहते रहे है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब ही मैने मुख्य मंत्री जी का ध्यान महेन्द्रगढ जेल में पंख लगाने की ओर दिलाया था। वहां पर पंखे नगे हुए है लेकिन वे खराब है। इसलिए पंखे होते हुए भी गर्मी में कैदियों को सड़ना पड़ता हैं जिस बैरक के अन्दर सजा पाए हुए कैदियों को रखा जाता है उस बैरक में भाँचालय नही है। कैदी को भाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बैरक में बन्द रहना पड़ता हैं उस दौरान अगर किसी को हाजत हो जाए तो पाखाना न होने की वजह से उसको बरामदे में भाँच करना पड़ता है। वहां पर ारे बदबू के नाम सड़ जाती हैं वहां टॉयलैट बनाने की बात पांच साल से ची रही है। मुझे खु ि है कि जब मैने चौधरी देवी लाल से, उनकी सरकार बनने के बाद, यह मांग की थी तो तत्काल उन्होने आदे ा दिए थे कि पंखे ठीक करवा दिए जाएं ओर पाखाना भी बना दिया जाएं। लेकिन मुझे ह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कि उनके आदे ा का आज तक भी पालन नही किया गया है। आज तक वहां पर पंख दुरुस्त नही हुए है और न ही वह

भाौचालय बनाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुडगावां और फरीदाबाद की एक ही जेल है और वह जेल पुराने अस्तबल में चल रही है। उस जेल में जितने कैदियों के रहने की व्यवस्था है उससे कहीं ज्यादा रह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गुडगावां और फरीदाबाद के लिए अलग-अलग जेल बनाई जाएं। फरीदाबाद में कोई जेल नहीं है, फरीदाबाद के कैदी गुडगावां की जूल में रखे जाते हैं। गुडगावां की जेल सोहना बस अड्डे के अपोजिट बनाई हुई है अगर उस जगह को बेच दिया जाए, उस जमीन को औक्शन कर दिया जाए तो उससे सरकार को करोड़ों रूपए मिल सकते हैं और जेल किसी दूसरी जगह पर बनाई जा सकती है। जो पैस उस जमीन को औक्शन करने पर सरकार को मिलेगा उस पैसे से फरीदाबाद और गुडगावां के लिए नई जेल का निर्माण हो सकता है और उनमें अच्छे भाौचालय बनाए जा सकते हैं तथा अन्य सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री द्वारा पेश किए गए इस सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूँ। अन्त में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो कैदी उनके काम को मेहनताना ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि उनके परिवार को कोई कष्ट न भोगना पड़े। जिन जेलों में स्थिति खराब है, उसको सुधारा जाए और साथ ही नई जेलों का निर्माण किया जाए। कैदियों से जो अधिकारी और कर्मचारी अपने घरों में नाजायज तौर पर काम करवाते हैं, उसको रोका जाए। सरकार मेरी इन बातों की तरफ

ध्यान देगी। इस आ आ के साथ मे इस सं गोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) विधेयक, 1988 प्रस्तुत किया गया हैं इससे पहले पंजाब सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) विधेयक, 1962 के तहत जो कैदीजेलों में होते थे, उनको सुविधाएं देने के लिए फरलों पर छुट्टी भेजने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था थी, वह था। लेकिन हमारी सरकार ने यह समझा और वास्तव में यह जरूरी भी था कि उसमें कुछ और बातें शामिल की जाएं क्योंकि समय के अनुसार परिस्थितियां बदली है। चाहे सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हो, परिस्थितियां बदलती है। इस प्रकार से बदलती हुई परिस्थितियायें में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री श्री नहर सिंह ढांडा ने यह जो सं गोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून की निगह में काइ जुर्म कर दें, तो उसको समाज मिलनी ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल भी जाए तो सजा मिलने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मानवता समाप्त कर दी जाए तो यह मानवता के प्रति एक अपराध जैसी बात होती है। यदि किसी व्यक्ति को सजा हो भी जाती है तो सजा भुगतने के दौरान उसके कुछ सामाजिक रि ते भी होते है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां भ्ज़ी होती है और उसकी आर्थिक परिस्थितियां भी होती है। इसदुनियादारी में उससे

संबंधित व्यक्तियों को, केवल उसको ही नहीं, उसके परिवार से संबंधित जो लोग हैं, उन लोगों को भी एक प्रकार से सजा हो जाती है। जिस व्यक्ति को सजा मिलती है, वह उसको पूरी भुगतेंगा लेकिन अगर उसका आचरण ठीक हो, उसका सदाचार ठीक हो तो उस विषय में यह जरूर देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसके लिए फरलो छुट्टी देने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर उसके परिवार में केवल वही व्यक्ति काम करने वाला हो तो उसको फसल काटने के टाईम पर या फसल की बुआई के टाईम पर फरलो पर टैम्पोरेरी छुट्टी दे दी जाए। कई बार ऐसी बात होती है कि जो व्यक्ति जेल में होता है, उसकी पत्नी या उसके बच्चे या खुद यदि बीमार हो जाए तो उसके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। जेल की परिस्थितियों के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार की होती है। जो लोग जेलों में रहे हैं, उनका पता है कि चार दीवारी के अन्दर रहना कितना भयंकर काम होता है और जो लोग जेल में रहे हैं, उनको भारीरिक्त ही नहीं बल्कि मानसिक यातनाएं भी बहुत होती हैं जिस व्यक्ति को होती है, केवल वही व्यक्ति इस बारे में जान सकता है। आप भी रहे होंगे और कई साथी भी जेल में रहे हैं। मेरह कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से यहां हाउस में आने से सभी मैम्बर आपस में एक साथी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जेल में रहने वाले लोग भी एक साथी की तरह ही हो जाते हैं हमारे नेता चौधरी देवी लाल जी का तो जेल जा का बहुत अधिक अनुभव है इसलिए मानवता के आधार पर इनकी हमें ऐसे लोगों के प्रति

सहानुभूति रही है। जेलों में ऐसा होता रहा है कि यदि जेल में हरने वाले व्यक्ति का कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए या उसकी डैथ हो जाये याओर कोई जरूरी काम हो तो भी वह किसी से नहीं मिल सकता था। इसी प्रकार से अगर किसी की लड़की की भाादी हो तो भी वह उस भाद में अब तक जा नहीं सकता था। इस संबंध में मैं भाायद गलती पर नहीं हूँ तो बताना चाहूंगा की ऐमरजैसी के दौरान चौधरी देवी लाल जी की पोती की भाादी थी लेकिन उन्हें उस भाादी में भाामिल होने के लिए जाने नहीं दिया गया था ऐमरजैसी के दौरान हमारे साथी श्री टेक राम जी और कई साथी थे, जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। उस समय चाहे कितना ही आवयक कार्य किसी को क्यों न रहा हो लेकिन उन्हें उस समय एक दिन के लिए भी जेल से पैरोल पर नहीं छोड़ा गया था। इन सारी बातों से प्रभावित हो कर ही यह विधेयक हमारी सरकार लाई हैं इस बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई बार नियम तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उनको ठीक प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया जाता। इस प्रकार कथनी और करनी में काफी अन्तर हो जाता है। और वेनियम केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं ऐसे नियमों को ठीक प्रकार से लागू करना ही सबसकी जिम्मेवारी बनती है। जो व्यक्ति चार दीवारी में बंद होता है, उसे तो पता नहीं होता कि उसके घर परिवार में क्या कुछ हो रहा है। अब तक ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं, बिना जेल अधीक्षक की अनुमति के किसी से मिल नहीं सकते थे। उसे चाहे कितनी ही यातनाएं जेल के अन्दर दी जाएं, किसी को कुछ पता नहीं चल

पाता था। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जेलों के अन्दर जो लैटरीन्ज की सुविधा है, पानी की सुविधा है या स्वास्थ्य संबंधी जैसे भुद्ध हवा की जरूरत है, सभी होने चाहिए ताकि जो सा उसे मिल है वह ठीक प्रकार से काट सके। कई बार पीने का पानी बहुत ही खराब आता है। अम्बाला जिले की जेल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं अम्बाला जिले की जेल में बन्द था तो उस समय उस जेल के पीने के पानी में काफी मिट्टी और तेल जैसा स्वाद अनुभव होता था। अब पता नहीं कि वहां का पानी ठीक कर दिया गया है या नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि इन सारी बातों की तरफ भी जेल अधिकारियों को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जेलों में जो फर्नीचर वगैरा है, उस परउनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। पहले भायद उन्हें ऐसा काम करने पर 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से दिए जाते थे लेकिन अब भायद एक रूपया का दिया गया है। इस संबंध में मेरे कहने का मतलब यह है जिस प्रकारसे किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को, बोनस वगैरा देकर, अतिरिक्त सहायता दी जाती है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी उनके किए गए काम में हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। कई कारखानेदार अपने मजदूरों को बोनस वगैरा इसलिए देते हैं कि उसके मजदूर काम अधिक और ठीक करें। इसी प्रकार से इन लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे भी अच्छा काम कर सकें। जेलों में ऐसे काफी लोग बन्द होते हैं, जो बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं और

उन्हें जो कुछ उनकी हिस्सेदारी मिलती है, उसे बचा कर अपने परिवार के पास भेजते रहते हैं इसलिए मेरी इसबारें में सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर अब य ध्यान दिया जाए। कई बार जेल अधीक्षक ऐसे लोगों से नाजायज काम भी करवते हैं जैसे यदि उनके अपने फार्म है या किसी रि तेदार का कोई कारखाना है, तो उन्हें काम करने के लिए भेजा जाता है। कई बार यह भी देखने में आया है कि यदि किसी बड़े व्यक्ति का किसी से वैर भाव होता है तो वह पुलिस से मिलकर उसे किसी झूझे केस में जेल मं बंद करवा देताहै और फिर उसी व्यक्ति से अपना बदलता लेने के लिए जेल अधीक्षक से मि कर अपने फार्म पर या कारखाने में काम करवाता है। इस बारें में भी सरकार को खासतौर पर देखना चाहिए कि जेलों में बंद लोगों के सथ कोई अन्याया न होने पाये। जो जेल अधीक्षक है, उनके पास काफी जमीन और काफी बड़े बड़े फार्म हैं जो उने पास रैजिउै गयल हाउसिज होते है, उनमें भी वे इन जेल में बंद लोगों से अपना काम करवाते है ओर घर की जमीन पर ही अनाज वगैरा पैदा करवतो हैं ऐसा काम होने पर न तो उस बन्दी को कुछ मिल पात है और न ही सरकार को कुछ मिल पाता हैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन द्वारा जो पैदावार की जाती है, उसमें से इनकों भी रहात दी जाती चाहिए। जितनी जमीन उनके मकानों के लिये जरूरी हो, उतनी ही जमीन दी जानी चाहिए। अगर उनके पास फालतू जमीन होगी तो वे जेल के कैदियों से उस पर काम

करवाते हैं। और उस जमीन से हजारों लाखों रुपये की आमदनी करते हैं।

इस विधेयक में और भी अनेक बातें हैं, जिनके बारे में कहूंगा कि हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है मैं सरकार से तथा श्री नर सिंह ठांडा से यह प्रार्थना करूंगा कि पुलिस के कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं और ठीक चीजें कई बार ढूँढने पर भी मिल नहीं पाती हैं। इसलिए नये सिरे से कोई कमेटी या कमीशन बना दिया जाए जो कि सारे विषयों की जांच पड़ताल करके कानून और पुलिस मैनुअल को नही सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाए। आज के जमाने में पुलिस नागरिकों के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाली संस्था होनी चाहिए। जो अपराधी है, उनके लिए जेलें तो होनी चाहिए लेकिन उन जेलों में उनके साथ जो व्यवहार उकों मिलना चाहिए। गुनाहगार को सजा अवश्य दी जाए लेकिन मानवता को समाप्त न किया जाए। इन भावों के साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मुझ बोलने के लिए आपने जो समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रत्न लाल कटारिया (रादौर—अनुसूचित जाति):
मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि इस सदन में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस मुल्क के अन्दर ऐसे हालात भी आए कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से सभी स्तम्भित रहे

गए। उदाहरण के तौर पर हिन्दुस्तान के न्दर एक बिहार राज्य हैं वहां की जेलों में कैदियों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ जिसे सुन कर रोंगटे खेड़े हो जाते हैं उस राज्य में एक स्थान है भागलपुर। वहां पर पुलिस ने कैदियों पर इतने अत्यचार किए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उनको अन्धा कर दिया। इस प्रकार के पुलिस के जुल्म, अत्याचारों और अमानवीय व्यवहार की घटनाएँ अक्सर सुनने में आती ही रहती हैं। इस बात को हरियाणा की लोकप्रिय सरकार ने महसूस किया है कि कैदियों के साथ मानवी सलूक होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की जालिम सरकारें भी आती रहती हैं जो कैदियों को रिलीफ देने की बजाए क्रूर तरीके अपना कर उनको परेशान करती हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हरियाणा की लोकप्रिय सरकार ने यह जो अमैण्डमैन्ट प्रस्तुत किया है, उसके अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कैदी जेल के अन्दर अच्छा बर्ताव करता है तो उसकी टैम्परेरी रिहाई की बात हो सकती है क्योंकि मैं पे से वकील हूँ इसलिए कई मामलों में बड़े दुःखद और अमानवीय वाक्या भी मैंने देखे हैं। कुरुक्षेत्र जिला की एक घटना का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूँ एक बुढ़िया के पांच बेटे थे जो कि एक मर्डर केस में इन्वोल्वड थे और जेल में बन्द थे। वह बुढ़िया अपने बच्चों की जुदाई का गम बर्दागत नहीं कर सकी और उसने दम तोड़ दिया। ऐसे दुःखद मौके पर यह कैसी विडम्बना थी कि पांच बेटों के हाते हुए भी उस बुढ़िया की अर्थी को कन्धा देने के लिए एक भी बेटा मौजूद नहीं था। इस

बिल में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी कैदी का व्यवहार अच्छा है तो वह अपने मासूम बच्चों को देख सकता है, जो उसकी जुदाई में शिक्षा के अभाव में रहते हैं। वह कैदी अपने घर की परिस्थितियों में सुधार कर सकता है उसके मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया हुआ होता है, जिसके कारण उनको उसकी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है और उसके रिश्तेदार पत्नी आदि उससे मिलने से वंचित हो जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, इन भावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हरनाम सिंह (गुवाहाटी): डिप्टी स्पीकर साहब समाज कल्याण मंत्री महोदय न जो हाउस के सामने बिल पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि यह कैदियों की रिहाई और पैरोल के बारे में है लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह बात भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को आम कैदियों के सुधार के बारे में भी विधेयक लाना चाहिए। जो लोग जरायम करके जेल में चले जाते हैं, उनके सुधार के बारे में भी कोई विधेयक आना चाहिए। कुछ लोग तो प्रोफ़ैशनल क्राइम करने वाले होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई लड़की हो गई, उसमें सजा हो गई या कोई कत्ल के जुर्म में सजा हो गई तो उनके लिए कोई न कोई विधेयक आना चाहिए ताकि वे अच्छे इन्सान बनें। उनके बारे में

हमें अलग से देखना चाहिए। उनके सुधार के लिए अलग से विधेयक लाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस विधेयक में मैं कुछ अमैडमेंट चाहता हूँ। इस विधेयक में परिवार के बारे में लिखा है कि ये ये लोग परिवार के सदस्य गिने जायेंगे। उसमें पुत्र-वधु और दामाद को भी शामिल किया जाये क्योंकि ये भी रिश्ते में दूर के नहीं होते हैं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि जब कैदी छुट्टी चला जाता है तो लेट पहुंचने पर इस बिल में उसे सजा की तजवीज है अगर कैदी एक दिन लेट आया तो अधिक से अधिक पांच दिन की माफी की कटौती होगी या एक महीने के लिए क्वैन्टीयन की सहूलियतें बन्द होगी या मुलाकात या चिट्ठी बन्द होगी। मैं समझता हूँ कि लेट पहुंचने पर यह सजा कैद की भावना में हो, नहीं तो डिसिपलिन बहुत कमजोर हो जायेगा। अगर कोई एक दिन लेट आता है और उसका जवाब तसल्लीबख्शा पाया जाता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर उसका जवाब तसल्लीबख्शा नहीं है और गलत है तो उसे दो गुने से पांच गुने तक यानी एक दिन लेट होने पर उसकी दो दिन की छुट्टी काट ली जाये और वह ज्यादा से ज्यादा पांच तक हो। वारनिंग वगैरह देना तो हौसला अफजायी ही होगी और अगर वह ज्यादा दिन रहेगा तो कल और भी ज्यादा सवाल पैदा हो जायेंगे। जेल में जहां हम सहूलियतें देने जा रहे हैं वहां डिसिपलिन भी मैनटेन करना चाहिए। अगर हमें

अपनी ने इन को और हरियाणा को बनाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। मैं भी कई बार पोलिटिकल बन्दी के तौर पर जेल में गया हूँ। वहाँ जो दिक्कतें हैं, वे मैंने देखी हैं। इसलिए आज के जमाने में जेल मैनुअल को तबदील करने की जरूरत है वह अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ है उसको बने हुए 80-90 साल हो गये हैं। अब मेरे पास स्पैसिफिक मद नहीं है जिसके कारण मैं यहाँ नहीं बता सकता। अगर जेल में ग्रेजुएट या पढ़ा लिखा चला जाये तो वे हर आदमी से अंगूठा लगवाते हैं। यह बात बहुत चुभती है। जब मैं जेल में गया तो झगड़ा भी हुआ। इसलिए मैनुअल को देखना चाहिये, उसको अमैड करना चाहिए। जेल के सुधार के लिए इन्सैन्टिव देना चाहिए हमें लोगों को अच्छी भाहरी बनाना चाहिए इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना कर लोगों से तजवीज मांगी जाये ओर दूसरा विधेयक बनाया जाये। इन भाब्डों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री मोहिन्द्र (रोहट): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सदाचारी बन्दी (अस्थार्ड रिहाई) विधेयक 1988 को माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया है मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। मैं मंत्री महोदय का धन्यवादी हूँ कि इस बिल में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यानी जिल से नागरिक वंचित रह जाते हैं, उन्हें देने के लिए सरकार यह

विधेयक लायी हैं उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1947 से पहले की परिस्थितियां कुछ और थी और आज की और है। आज हर नागरिक उन असुविधाओं और अनियमितताओं का विरोध करना चाहता है जिने बारें में यह सोचता हूं कि उससे उसे दबाया जा रह है। इस विधेयक में एक क्लॉस 6 है। धारा 3 और 4 के अधीन बन्दी कुछ दिन की रिहाई के हकदार होंगे और कुछछशा में बन्दी रिहाई के हकदार नहीं होंगे। राज्य सरकार द्वारा उनकी यात्रा के लिये खर्चा उठाया जाना, एक ऐसा प्रोविजन है, जो वकाई तारीफ के काबिल हैं मैं हरियाणा सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उसने इस बात को ध्यान में रखा है जैसे हीरा नन्द आर्य जी ने बताया कि मानवता के आधार पर भी यह बात कंसीडर की जानी चाहिये थी, जो कंसीडर की गयी हैं मैं हरियाणा सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के पास होने के बाद हमारा प्रदे 1 पहले नम्बर पर आ जायेगा जिसने दे में ऐसा कदम उठाया है। अन्तं में मैं इस विधेयक की तारीफ करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं एक दो सुझाव भी अपनी तरफ से दना चाहता हूं। फरीदाबार जिले के अन्दर अब तक इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोई भी जेल नहीं है फरीदाबाद के नन्द अगर किसी को किसी भी जुर्म में सजा हो जोय तो उसको रोहतक जेल में भेजते है, गुडगावं जेल में भेजते

है या फिर अम्बाला जेल में भेजते हैं। चाहे किसी को सियासी केस में जेल भेजा जाये, किसी मर्डर केस में या चोरी के केस में भेजा जाये, वह सजा उसके परिवार को मिली है उसके परिवार को रोहतक जाना पड़ता है या गुडगावां जाना पड़ता है। मैं यह कहूंगा कि फरीदाबाद के अन्दर भी कोई न कोई जेल बननी चाहिये। मैंने पिछले दिनों एक बात देखी। फरीदाबाद के अन्दर सजा होने के बाद, उसके परिवार को और उसके साथियों को काफी दिक्कत होती है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले के अन्दर कोई न कोई जेल अवश्य होनी चाहिए क्योंकि आज तक वहां पर कोई जेल नहीं है अन्त में मैं यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी लोकप्रिय सरकार जो चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में चल रही है, ने जन कल्याण के लिए बहुत ही प्रभावी और दूरगामी कदम उठाया है इस विधेयक के माध्यम से बहुत सी सुविधाएँ दी गयी हैं पंजाब ऐक्ट 1962 में जो सुविधाएँ दी गयी हैं उनको और ज्यादा रिलैक्स करके रिहाई की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसके लिये समाज कल्याण मंत्री बंधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से हमें सबसे पहले इस प्रश्न में जाना होगा कि इन जेलों के नाम समाज सुधार गृह क्यों रखा गया है? इस कानून को बनाने का मकसद भी यही है यह विचार उभर कर सामने आता है कि हमारे यहाँ समाज में या

स्वच्छ समाज में इतने दिन गुजारने के बाद भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं कि उन पर अंकुश लगाने के लिये भासन को समाज में कानून व्यवस्था सुधारने के लिये और उसको मेनटेन करने के लिये कानूनों की आवश्यकता पड़ती है चाहे या अनचाहे मैं उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों का कानून के मुताबिक सजा दी जाये। जैसे कि आप स्वयं भी जातने हैं, हमारे सभी विधायक साथी और जनता इस बात से परिचित है कि बहुत से केसिज में कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जब दिल और दिमाग में या मनप व मस्तिष्क में कोई ऐसी बात नहीं होती और परिस्थितियां या कारणों का वह काम हो जाता है। इसमें जो असीर्ई रूप से बन्दियों को रिहाई का रिलीफ दिया गया है, यह ठीक बात है इसमें जो सुविधा दी गयी है, जो प्रोवीजन किया गया है कि किसी विशेष परिस्थितियों में सरकार की तरफ से टैम्पोररी रिलीफ दिया जाये, यह वास्तव में बहुत ही प्रोसनीय कदम है। जिस तरीके से यह किया गया है यह काबिले तारीफ है कि बन्दी की फैमिली में अगर किसी की मृत्यु हो जाये या वह स्वयं बीमार हो जाये या उसकी फैमिली में से कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उसको तीन सप्ताह तक रिहा किया जा सकता है। यह रिलीफ उसको हो सकता है। अगर बन्दी की फैमिली के सिरी आदमी की गादी है या उसकी अपनी भाादी है तो उसको चार सप्ताह तक रिहा किया जा सकता है। इसक अलावा खेती व्यवस्था सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिये उसकी रिहाई 6 सप्ताह तक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई अत्यन्त आवश्यक काम होगा तो इस

बिल में चार सप्ताह की रिहाई का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय में जेलों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी लेकिन जब भारत स्वतन्त्र हुआ है, जेलों की व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है लेकिन अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि ऐक्सपर्ट्स की एक साइकौलोजी कमेटी बना दी जाए तो रिलीफ देने के समय यह सावधानी बरते और यह देख ले कि लोगों को छोड़ना जा रहा है, उनके मन में दूसरे लोगों के प्रति कोई रंजित तो नहीं है जिससे कहीं ऐसा न हो कि वे छूटकर समाज में कोई परेशानी खड़ी कर दें और जिन लोगों के प्रति उन छूटने वालों के मन में कोई रंजित है, उनको कोई कष्ट दें। यह मेरा एक सुझाव है उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

जेल राज्य मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा): डिप्टी स्पीकरसाहब, आदरणीय चौधरी देवी लाल की सरकार ने यह जो बिल सदन के सामने रखा है यह बहुत अच्छा बिल है सभी माननीय सदस्यों को पता भी है कि चौधरी साहब खुद बहुत सालों तक जेलों में रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भूख नहीं देखी उसको भूख का पता नहीं होता। केवल भाषण देने से भूख का अनुभव नहीं होता। चौधरी देवी लाल ने बहुत साल अपनी जिन्दगी के जेलों में बिताए हैं और उन जेलों की हालत देखकर ये सारे सुझाव उनके मन में आए और इस बिल के रूप में इस सदन में प्रस्तुत किए गए हैं। सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन

किया है, लेकिन कुछ बातें सामने आई हैं रघु यादव, हीरा नन्दआर्य, भगवान सहाय रावत और कटारिया साहब ने कुछ सुझाव दिए हैं यहां पर कहा गया है कि महेन्द्रगढ़ जेल में चौधरी साहब ने पंखे लगवाने का आर्डर दिया था लेकिन वे लगे नहीं हैं। इसकी इंक्वायरी करवा लेगे और जिसकी गलती होगी उसको सजा देगे। एक बात यह कही गई कि मजदूरी बहुत कम है और यहकेवल आठ आने हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह मजदूरी अब तीनचार रूपये के बीच में कर दी गई है। इसी तरह से रघु यादव ने कहा कि जेलों में ऐनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राहेतक ओर हिसार की जेलों को देखा जाए तो पता लगे कि वहां बहुत बढ़िया ऐनवायरमेंट हैं वहां पर फूल लगे हैं और छोटे बगीचे बनाए हुए हैं। जो नई जेलें बन रही हैं, उनमें ये सारी चीजें बनई जा रही हैं और ऐनवायरमेंट को बढ़िया बनाया जा रहा है। जहां तक मिलने की बात है मिलने का टाईम ज्यादा दिया जाता हैं और बाहर भौड बना दिए हैं। जो भी मिलने के लिए जाता है उसको पूरी सहूलियत दी जाती हैं जो पीछे कानून थे, वे अंग्रेजों के टाईम के थे। 1962 का जो ऐक्ट बना हुआ था उसको कुछ सिम्पलीफाई किया हैं आर्य साह ने कहा है कि कानूनों में सुधार किया जाए। मैं आर्य जी से अनुरोध करुंगा कि वे इस बारे में अपने सुझाव ला कमीशन को भेज दें। सुझावों को देखकर विचार किया जाएगा कि क्या सुधार किया जा सकता है। कटारिया साहब ने कहा कि बीमारी की हालत में तुरन्त रिहाई की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर लिखा है कि तुरन्त रिहाई की जाएगी और

इसके लिए जो भी अफसरमौके परहोग, उसके पास राइट होगा कि वह उस आदमी को जल्दी रिहा कर दे और जिस मौके पर उसे पहुंचना है, वह आसानी से पहुंच सके। उपाध्यक्ष महोदय, सभी मैमबर्ज ने इसका समर्थन किया है है डाक्टर हरनाम सिंह जी ने बोलते हुए भाादी की व्यवसीा रखी है रघु यादव साहब ने बोलते हुए कहा कि कोई दोशी तो जेल चजा जाता है लेकिन कई बिना दोश किये ही जेल चले जाते हैं इसके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए। मै यह बताना चाहता हूं कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही हम किसी को जेल में बन्दर करते है। उस फैसले के खिलाफ हम नहीं जा सकते। उन्ही फैसलों के अनुसार ही हमें कैदियों को जेल में रखना पडता है और उन कैदियों का जेल में सुधार किया जाता हैं।

इससे आगे एक और बात इस सरकार की यहां बताना चाहता हूं। हमारे सत्ता में आने से पहले जेलों में कैदियों को दूध वगैरह नहीं दिया जाता था। अब हमारी सरकार ने हर कैदी के लिए एक पाव दूध रोजाना देने की व्यवस्था की हैं यह बड़ा ही सरहानीय काम है। यहां तक ही नहीं बल्कि हमने जेलों और सब-जेलों में टी0 वी0 सैट्स और टू-इन-वन भी दिये है। साथ ही सथ ऐम्बुलैन्स बैन्ज की भी डिस्ट्रिक्ट जेलों में प्रबन किया गया है ताकि किसी ऐमरजैन्सी में उस वैन का प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार से अब जेलों के अन्दर और भी सुख-सुविधाएं प्रदान की गयी है।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, क्या टी0 वी0 सैट्स और टू-इन-वन मंत्री महोदय ने अपनी भाादी के मौके पर तो नही पहुंचाए है।

श्री नर सिंह ढांडा: ये पहले के है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, इन सभी बातों को सरकार ने अपने ध्यान में रखा है। जहां तक जेल मैनुअल की बात है, उसको जल्दी ही बदला जाएगा और जा पुरानी बातें है, उनमें जल्दी से सुधार लाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत सरकार फील करेगी, तो उसकी जल्दी ही दूर किय जाएगा। मैं यहां सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई और सुझाव हो, या कोई ऐसी बातें हो जिन से जेलों में सुधार लाया जा सके, तो वे अपने सुझाव अव य हमें भेजें हम उनको स्टडी करेगे और उन पर पूरा पूरा विचार किया जाएगा। इन भाब्दों के साथ, मैं हाउस से यह प्रार्थना करूंगा कि इस सं गोधन बिल को पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause

Sub-clauses (2) & (3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That sub-clauses (2) & (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 5

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 6

Mr. Deputy Speaker: Question is—
That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 7

Mr. Deputy Speaker: Question is—
That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 8

Mr. Deputy Speaker: Question is—
That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 9

Mr. Deputy Speaker: Question is—
That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 10

Mr. Deputy Speaker: Question is—
That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 11

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Dr. Deputy speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Jails (Sh. Nar Singh Dhanda): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed

The motion was carried

(iii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिड अमैडमेंट)

बिल, 1988

श्री उपाध्यक्ष महोदय: अब ऐक्साइज एंड टैक्से इन मिनिस्टर साहब दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिड अमैडमेंट) बिल, 1988 इंट्रोड्यूस करेगे और यह प्रस्ताव करेगे कि बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain):

Sir, I beg to introudce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill 1988.

I also move-

That the Haryana General Sales Tax (Secound Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Secound Amendment) Bill be taken into consideration at onec.

श्री मंगल सैन (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, राव राम नारायण जी ने सदन में जो बिल पारित करने के लिए रखा है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे ये बुजुर्ग कराधान विभाग के मंत्री हैं। इस बिल पर मैं अपनी बात कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रो० सम्पत सिंह जब इस डिपार्टमेंट को देखते थे तो उस नवयुवक मंत्री ने काफी ऐसे परिवर्तन किए थे जिससे व्यापारियों को राहत मिले। समाज का हर वर्ग उपयोगी है, महत्सपूर्ण है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर, तीनों वर्गों का अपना अपना स्थान है मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने कुछ दिनों में ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आकर व्यापारियों को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है एक फार्म 38 नम्बरका और लगा दिया है। मैंने सुना है कि कोई ऐडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है सुना इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी स्थिति ऐसी है और खास करके अपनी स्थिति ऐसी है कि हमारे से कुछ न कुछ सलाह करने का मतलब ही नहीं है, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। उसमें व्यापारियों के प्रधान, हिसार निवासी, दाल वाले हैं, जो अब बेसन वाले भी हो गए हैं। उनहोंने ध्यान दिया है कि साहब हमसे पूछा तक नहीं। मुझे यह बात पढ़ कर बड़ी हैरानी हुई कि यह कैसे हो गया? डिप्टी स्पीकर साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उसको तुरन्त खत्म किया जाना चाहिए। इस विधेयक में कम्बल और हैडलूम के सामान के बारे में भी फरमाया गया है। इस बारे में मेरी एक काल अर्टिकल भी थी जिसमें मैंने अंडरवियर और बनियान के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि हमारे भाहरों में धरेलू

उद्योग धंधों में काफी महिलाएं लगी हुई हैं जो छोटे छोटे कपड़े सिलती हैं अगर उन पर टैक्स लगा दिया गया तो हमारे रोहतक की मंडी तो बिल्कुल उजड़ जाएगी। उधर राजस्थान में इस पर टैक्स बहुत कम है, दिल्ली में कम है ओर पंजाब में कम हैं अगर उन पर टैक्स लगा दिया गया तो उनको लाईसैन्स लेना पड़ेगा। हरियाणा का इंजीनियरिंग माल हरियाणा में ही रहे और उसको हरियाणा की जनता ही इस्तेमाल करें उन पर टैक्स लगाने से कहीं ऐसा न हो कि हरियाणा के नौजवान लड़के दिल्ली से सामान लेने के लिए रात को रेल में पलवल, रिवाड़ी, सोनीपत और फरीदाबाद की ओर से जाएं और वहां से सामान ला कर हरियाणा में बेंचे। हजारों छोटे छोटे नौजवान लड़के अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं हमारे प्रदेश के बेरोजगारी के बारे में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो प्रोफैसनल लोग हैं, वकील हैं, डाक्टर हैं और इंजीनियर हैं, वे बकाए घूम रहे हैं। थोड़े पढ़े लिखे का तो बहुत बुरा हाल है। जो हमारे प्रदेश में बेरोजगार हैं, उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता तो दे नहीं सकती क्योंकि इनका पैसा कहां से आए? डिप्टी स्पीकर साहब, यदि उन पर टैक्स लगा दिया गया तो यह एक परेशानी का कारण बन जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात यह कही गई है कि जो दुकानदार एक लाख रूपए तक कम्बल बेचेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन उसको कम्बल बेचने के लिए लाईसैन्स जरूर लेना पड़ेगा। ऐसा करके इंस्पेक्टर को दुकान पर चढ़ने का मौका दे दिया गया है डिप्टी स्पीकर साहब, आपको इस बात का तजुर्बा

है या नहीं मुझे इस बारे में पता नहीं लेकिन इंस्पैक्टर को एक बाद दुकान पर जाने का मौका मिल जाए तो वह अपनी दिहाड़ी बनाने से बाज नहीं आता। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री मास्टर बनारसी दास गुप्ता जी बैठे नहीं हैं, उन्होंने कल सदन में कहा था कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे बन्द कर रहे हैं।

श्री रघु यादव: वे मास्टर नहीं, लाला हैं। (व्यवधान और भाोर)

श्री मंगल सैन: वे मास्टर ही हैं और यदि उनको लाला भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। वे पुराने स्वतन्त्रता सेनानी हैं and I have every regard for him. यादव साहब, लाला कहना भी उनके लिए इज्जत का प्रतीक है Do not use it in a contemptuous way. It is very bad. (Interruption) मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे परे गानी बढ़ने वाली बात हैं ऐसा करके आपने इंस्पैक्टर को दुकान पर चढ़ने को मौका दे दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, व्यापारियों ने हम सबों यहां लाने में बड़ी मदद की हैं यह सरकार अव्यापारी, किसान, मजदूर और आम आदमी के सहयोग से बनी हैं उस संघर्ष में छोटे दुकानदारों का भी सहयोग रहा हैं उनको इंस्पैक्टर के चगुल में कया फंसाया जा रहा है? राव साहब, बुजुर्ग आदमी है तजुर्बेकार है और वे ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं भायद हरियाणा बिजली बोर्ड के सैक्रेटरी रहे हैं वे भुक्षा तबीयत के आदमी हैं। मैं इनसे इलतजा करूंगा कि ये इसको ड्रौप करें। एक बात यह भी कही गई है कि यदि कोई व्यापारी को जुर्माने से

डर नहीं लगता उसको कैद से डर लगता है। आप कोई ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाए तो हर व्यापारी अपना हिसाब ठीक रखेगा। अगर ठीक न रखे तो उसको ऐसा कोई दण्ड दिया जाए तो सुहालात सुहता हो। आपने व्यापारियों को जो सुविधाएं दी थी, उन परकायम रहे। व्यापारियों ने कई नेताओं को पैसों से तोला भी था, सम्मेलन भी किए थे तथा उन्होंने पुरियां भी खिलाई थी, इसलिए कम से कम उनको इस परे पानी से दूर करों। उनको आपने जो सुविधाएं दी थी उनकी उसी तरह से कायम रहने दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने बुजुर्ग राव साहब से प्रार्थना करूंगा कि मैम्बरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बारे में विचार करें।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, राव साहब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इस पर मैं आपने विचार प्रकट करने के लिए खडत्रा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में बनने के बाद व्यापारियों को काफी सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं और व्यापारियों को राहतें भी दी गई हैं। यदि उन राहतों की चर्चा, मैं यहां पर इस समय करूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। हमारा सरकार ने सोयाबीन मिल को टैक्स मुक्त किया और जो मैनुफैक्चरिंग गुड्स है, उन पर भी सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स वापस लेने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं साथ ही साथ साधारण व्यक्ति के प्रयोग में आने वाले नमक को भी करमुक्त किया है हले नमक

की थैलियों पर टैक्स लगता था, उसे अब बिल्कुल समाप्त कर दिया है इसी प्रकार से हलवाईयों तन्दूर-ढाबों आदि पर जो टैक्स पहले लगता था, उसे वापस लेकर इन लों को राहत दी है इसी प्रकार से हाथ से बनी हुई चीजों पर जो टैक्स लगता था, उन आईटमों पर भी 5.5.1973 से टैक्स से राहत दी है (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) आयल पर पहले 6 परसेन्ट टैक्स लगता था, जिसे घटा कर 2 परसेन्ट किय गया है इसी प्रकार से लकड़ी पर भी 12 परसेन्ट से 8 परसेन्ट टैक्स किया गया है। स्टैनलैस स्टील की आईटमों पर 12 परसेन्ट और 8 परसेन्ट टैक्स लगता था अब हमारी सरकार ने इन सभी पर 12 परसेन्ट और 8 परसेन्ट की बजाये 3 परसेन्ट टैक्स किया है। इसी प्रकार से व्हीकलज की चैसिज पर जो टैक्स 10 परसेन्ट था, उसे हमारी सरकार ने घटा कर 4 परसेन्ट किया है। कम्बलों पर भी हमारी सरकार ने 4 परसेन्ट से कम करके 2 परसेन्ट टैक्स किया है जूट के बने हुए बैग्ज पर पहले 8 परसेन्ट टैक्स लगता था उसे भी घटा कर 4 परसेन्ट किया गया है। इसी प्रकारसे सीमेन्ट और टायर और दूसरी कई चीजों पर जो सेल्ज टैक्स 12.80 और 8 परसेन्ट टैक्स लगता था, उसे भी काफी घटाया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से काफी सुविधाएं व्यापरियों अनेक राहते देने के बावजूद भी कहां पर औरकिस जगह गड़बड़ है जो तालमेल आपस में दोनों का होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हो पाया है हमें इसके कारण जानने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहां परयह जो विधेयक प्रस्तुत

किया गया है इसमें डा० साहब ने फार्म-38 के बारे में चर्चा की है। क्योंकि मैं तो व्यापारी नहीं हूँ इसलिए मुझे फार्म-38 के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान ही है। लेकिन इस फार्म के बारे में मैंने व्यापारियों में चर्चा अवश्य सुनी है मैं समझता हूँ कि कर के जो नियम हैं जितने सख्त होंगी और जितना ज्यादा टैक्स होगा उतनी ही टैक्सी की चोरी होगी। यदि सिटी चीज पर 10-12 प्रतिशत टैक्स लगता हो तो व्यापारी हमें आपकी बचत की बात सोचता है और वह बेइमानी से टैक्स बचाता है। जो ईमानदार व्यापारी है, उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि टैक्स 10 या 12 प्रतिशत है तो व्यापारियों की हमें यह प्रवृत्ति रहती है कि वे इस टैक्स का 4 या 5 प्रतिशत भाग भ्रष्ट तरीकों से खर्च कर 6 या 7 प्रतिशत टैक्स की चोरी कर ले। यह 4 या 5 प्रतिशत वे इन्सपैक्टरों पर, ओर बैरियर आदि पर चोरी करके और इन्कम टैक्स वालों के अधिकारियों को रिश्वत आदि के रूप में देकर खर्च करते हैं और उसके एवज में टैक्स की चोरी करते हैं। इस प्रकार व्यापारी लोभवत् सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से मिली भगत करके उन्हें भ्रष्टाचार के लिए उकसाते हैं जिससे भासनतन्त्र भ्रष्ट होता है। ज्यादा टैक्स दर होने से टैक्स की चोरी ज्यादा होती है जिन राज्यों में टैक्स की दरें कम हैं, उन राज्यों का टैक्स राजस्व ज्यादा टैक्स दर रखने वाले राज्यों से की अधिक है। दूसरे प्रांतों में जहां टैक्स दरें कम हैं। वहां टैक्स से होने वाली इन्कम बढ़ी ही है। इसलिए व्यापारियों पर टैक्स की दरें कम करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। जो विधेयक इस समय सदन में

रखा गया है, उसमें मुख्य रूप से तीन बातों में अमैण्डमेंट की गई हैं सबसे पहले बात जनवरी, 1988 से पहले कम्बलों पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बादमें सरकार ने इस आईटम् पर टैक्स लगाया है जो कि उचित बात है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिस व्यापारी की कम्बालें को टर्न ओवर एक लाख रूपये से अधिक वार्षिक होगी, उस पर यह टैक्स लगाया जाएगा। इस प्रकारका संशोधन इस बिल की धारा 6 में प्रस्तुत है। दूसरी बात इस बिल की धारा 13 में एक क्लॉज जोड़ी गई है जिसके अनुसार हरियाणा जैसे कृषि प्रधान प्रदेशों में भी उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। कृषि प्रधान देशों में यदि इंडस्ट्री और उद्योग धंधे नहीं होंगे तो उसकी उन्नति नहीं हो सकेगी। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो नई औद्योगिक नीति घोषित की है, उसमें सरकार ने उद्योगपतियों को कुछ रिलीफ दिए हैं ताकि आने वाले समय में प्रदेशों में अधिक से अधिक इंडस्ट्री और उद्योग-धंधे स्थापित हो सकें। इस औद्योगिक नीति के तहत ही यह क्लॉज जोड़ी गई है।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, आप जल्दी ही वाइण्ड अप करें।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धारा 14 में जो संशोधन किया गया है उसमें यह है कि कोई कोर्ट का फैसला था और अदालत

का वह फैसला सरकार के खिलाफ था। यदि सरकार पिछली तारीख से अमैडमैट ने करें तो सरकार को लगभग 50 लाख रूपये का घाटा आत है। इस घाटे की बचाने क लिए ही सरकार ने यह सं गोधन प्रस्तुत किया हैं एक अगला सं गोधन जो बिल द्वारा किया गया है। वह यह है कि अगर कोई व्यापारी इन्कम टैक्स इन्सपैक्टर या किसी अधिकारी को अपनी दुकान के बही खाते या रिकार्ड वगैरा नही देता, क्योंकि जो व्यापारी नम्बर-2 का काम करते है। वे अपनी सारी नम्बर दो की कितबे किसी दूसरी जगह पर रखते है, तो अधिकारी ऐसे व्यापारी को दो हजार से पांच हजार रूपये तक का जुर्माना करसकते हैं इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस धारा से की भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जो रूलज और नियम निर्धारित किये गये है, उनका सख्ती से पालन हो। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इलैव इन के समय हमने जनता से यह वायदा कियाथा कि हम इन्सपैक्टरी राज को खत्म करैगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कही इससे इन्सपैक्टरी राज को बढ़ाया न मिले। इसलिए इस बिल की धारा पर पुनविचार करके इस बड़ी सावधनी से इस्तेमाल करना होगा ताकि भ्रष्ट इन्सपैक्टर या अधिकारी व्यापारियों से जबरदस्ती पैसा इकट्ठा न करने लगे। हरियाणा सरकार ने कई बार व्यापारियों से बातचीत के लिए एक कमेटी बनायी हुई है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर उनसे विचार-विर्म 1 किया जा सकता हैं और व्यापारियों को सहूलियतें दी जासकती हैं राव राम

नारायण जी हमारी इस सरकार मे बहुत ईमानदार मिनिस्टर है। इसलिए उन्हें ईमानदारी से कार्यवाही करके प्रशासन को ठीक प्रकार से चलना चाहिए ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो।

श्री शिव प्रसाद (अम्बाला भाहर): अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़े समय के अन्दर दो चार बातें मैं आपे द्वारा मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस बिल में लिखा है कि जो व्यापारी अपना हिसाब-किताब नहीं रखेगा, उस पर असैसिंग अथोरिटी दो से लेकर पांच हजार तक पैलन्टी लगा सकती हैं बड़े दुकानदार और फ़ैक्टरी वाले तो अपना हिसाब किताब रख सकते हैं। लेकिन छोटे दुकानदार न तो स्वयं हिसाब रख सकते हैं और न ही वे मुनीम रख सकते हैं। ऐसा करके तो छोटे दुकानदारों को इन्सपैक्टर्ज के चंगुल में फसाने वाली बात है। आजकल 50, 60, 70 और 80 रूपये का कम्बल आम गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। अम्बाला भाहर में होलसेल कपड़े की मार्किट हैं इस कपड़े की मार्किट के साथ सारा हिमालय प्रदेश जुड़ गया हुआ है और अम्बाला के आस-पास के लोग भी वहांसे माल लेने के लिए आते हैं। वे लोग वहां से छोटे-मोटे कम्बल वगैरहा भी ले कर जाते हैं अगर कोई हिमाचल का छोटा व्यापारी वहां पर माल लेने के लिए आता है तो वहां कपड़े के साथ-साथ कम्बल वगैरहा भी खरीद लेता है। वह व्यापारी कपड़े की गांठ के अन्दर ही कम्बल वगैरहा भी बन्धवा लेता है अगर वह व्यापारी वहां से माल लेकर चला गया और उसे बैरीयर पर चैक कर लिया गया और उसकी गांठ को खुलवा लिया

तो उस गांठ को न कोई वहां पर बान्धने वाला मिलेगा और न ही चढ़ाने वाला मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये जो कम्बल और भाल के बीच में ले आये है, ये नहीं लेने चाहिए। पहले कपड़े पर कोई टैक्स नहीं होता था इसलिए इस बारे में फिर से सोचा जाये ताकि हरियाण के लोग इस परे ानी से बच जाये। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल और इधर उधर का सारा इलाका अम्बाला से कपड़ा खरीदता था लेकिन अब वे लोग हरियाणा से माल न खरीद कर चण्डीगढ़ और सहानपुर से माल खरीद कर ले जायेगे और हरियाणा प्रदे ा को जो छोटी-मोटी इन्कम होती थी, वह भी खत्म हो जायेगी। जिसके कारण हरियाणा को नुकसान होगा।

एक दूसरी बात मैं मंत्री महोदय के नोटिस में और लाना चाहता हूं। जैसे हौजरी वाले है जो अच्छा बनियान बनाते है उन पर तो पहले ही टैक्स लगा हुआ है। आपको पता है कि गरीब आदमी ही कच्छा बनियान इस्तेमाल करते हैं सड़क पर काम करने वाला, रिक् ा चलाने वाला और रोड़ी कूटने वाला आदमी कमीज पाजा न पहन कर कच्छे बनियान में काम करता है। इसलिए ऐसा करने से गरीब आदमी पर ज्यादा असर पड़ेगा। मेरा मकसद यह है कि ऐसा करने से आस पास के प्रांतों को आमदनी होगी और जो हमारी स्टेट को आमदनी होनी थी, वह नहीं होगी। आस पास के प्रांतों को देख कर अपनी स्टेट की आमदन बढ़ाने क लिए टैक्स लगा दिया जात है। सरकार यह देखती है कि दिल्ली,

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसचीज पर कितना टैक्स है, उसे देख कर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन बढ़ाने के बाद उतनी आमदनी नहीं होती। उससे परे पानी और भ्रष्टाचार बढ़ता है हमारे यहां अम्बाला से दिल्ली डेली पैसेन्जर हैं वे दिल्ली से पानीपत और पानीपत से अम्बाला तक पास बनाव लेते हैं और वे रोजना सामान लाते हैं। जैसे चप्पल और दूसरी चीजों पर सी0 एस0 टी0 लगा है, कहीं टैक्स लगा है और कहीं सर चार्ज लगा है, इस प्रकार वह 12-14 परसेन्ट बन जाते हैं इस प्रकार से जो लोग माल लेकर दिल्ली से आते हैं वह दुकानदार को तीन या चार परसेन्ट टैक्स पर माल दे देते हैं तब तो उनका यह पैसा हरियाणा में सेल्ज टैक्स के रूप में आता है और नहीं हरियाणा की आमदनी बढ़ती है इसबहाने वह माल चोरी से लाते हैं। म्यूनिस्पल कमेटी की सीमा में जब वे दाखिल होते हैं तो वे औक्ट्राय भी नहीं देते। इससे कमेटी को औक्ट्राय की इन्कम में भी कुक्सान होता है। मेरा कहना यह है कि चाहे वह कच्चा तहो या बनियान हो, चाहे वह जूते का सवाल हो, इन पर टैक्स नहीं होना चाहिये। प्लास्टिक के 25-30 रुपये के जूतों पर जैसे कि हमारे बराबर की स्टेअ में टैक्स माफ है हमारे यहां भी माफ होना चाहिए। हमारे यहां पर इनके ऊपर टैक्स है। हमारी सरकार ने यह कई बार एलान किया है चाहे वह गांव का रहने वाला है, किसान है, मजदूर है या वह दुकानदार है, उनको सब को रहात देनी है सब की नुमायंदगी हम लोग करते हैं। मेरा तो सुझाव है कि आप भी कम से कम 25-30 रुपये की चप्पलों या जूतों को इस टैक्स

की सीमा से निकाल दे ताकि आम लोगों को रहत मिल सके। पिछले दिनों बूरे के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। घरों में बूरा कुछ लोग लकड़ी के कूटते हैं कूटने के बाद उसको बेचते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। राजस्थान की सीमा के साथ लगते हुए हमारे कुछ इलाके हैं। वहां पर लोग 10-15-20 सेर बूरा ले आये, उससे ऊपर टैक्स नहीं है अब लोगों ने बूरा कूटने वाले मजदूरों को हटा दिया वे कहते हैं कि अब हमें बूरा बनाने की जरूरत नहीं है अब तो हम राजस्थान से बूरा लेगे। मेरा कहना यह है कि हमारी हरियाणा सरकार को पैसे का भी ध्यान रखना चाहिए लेकिन इसके साथ ही साथ गरीबों को भी राहत देनी चाहिए हमारे नेता ने कहा तो है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं लेकिन इस तरह से तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जितने टैक्स आप बढ़ायेगे, उतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जितने टैक्स कम होंगे उतना भ्रष्टाचार घट जायेगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार की आमदनी ज्यादा हो सके, इसके लिए मैं आपको द्वारा कुछेक सुझाव देना चाहता हूँ एक हमारे यह धूलकोट बैरियर है और एक देवीनगर जी0 टी0 रोड पर बैरियर है इनके लिए कोटा मुकर्रर कर दिया गया है कि पैनल्टी का 35 हजार रूपया धूलकोट वाला बैरियर इकट्ठा करके देगा और 70 हजार रूपया देवीनगर का बैरियर इकट्ठा करके देगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक लाख रूपया इन्होंने केवल इन दो बैरियर के लिए मुकर्रर कर दिया है इससे वहां पर रिक्त का सिलसिला भुरू हो जायेगा। पैनल्टी लगने के बाद क्या दिक्कत आत है, वह भी जरा सुन ले। जिसके ऊपर पैनल्टी

लगती है, वह एप्लाइ करता है कि उसको आर्डर की एक नकल दी जाये ताकि वह उसके अर्गेस्ट अपील कर सके। एक एक साल पुराने ऐसे केसिज अभी तक पडत्रे हुए है, जिनको पैनल्टी लगने के बाद आज तक भी नकल नहीं मिली है। अगर मैं उनकी डिटेल बताने लगूंगा तो ज्यादा समय लग जायेगा। इसबारे में एक सुझाव मैंने पहले भी दिया था। वह सुझाव यह है कि अपीले सुनने के लिये एक ट्रिब्यूनल दो जगह होना चाहिए। एक फरीदाबाद में और एक अम्बाला में ट्रिब्यूनल दो जगह होना चाहिए। एक फरीदाबाद में और एक अम्बाला में ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि लोगों को कुछ सुविधा हो सके। अब अफसर एक जगह रख दउते है कि आप यहां पर आ जाये। आदमी सैकड़ो रूपये खर्च करके वहां पर आते है। कई बार उस दिन बाई चांस वह अफसर वहां पर नहीं पहुंचता तो उस दिन आदमी को वहां से वापिस जाना पड़ता है ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। हमारे हरियाणा के खजाने में किस तरीके से ज्यादा पैसा आये, इस प्रकार की याजना जरूर बनाये। मैं नहीं कहता लकिन आम लोगों को कहना यह है कि भ्रष्टाचार खत्म होने के स्थान पर सरकार की इन नीतियों से यह बढ़ता भुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए।

श्री शिव प्रसाद: ठीक है जी, धन्यवाद।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, राव राम नारायण ने हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 विचार करने के लिए ओर पारित के लिए पे 1 किया है। इसमें जो स्वागत योग्य बात है, वह धारा 13 बी का जोड़ना है। इसके अनुसार हरियाणा में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नए उद्योग हरियाणा में लगे और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नए उद्योग लगाने वाले जब उत्पादन शुरू करें तो कुछसमय के लिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बिक्री कर से छूट दी जाए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वर्ष इस धारा 13 बी जुड़ जाने के बाद हरियाणा में औद्योगिक विकास तेज होगा और उसे बल मिलगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जिसजिले से मैं आता हूँ वह बहुत ही पिछड़ा और उपेक्षित जिला है। जिला महेन्द्रगढ़ में, इस सरकार से पहले जो कांग्रेसी सरकार थी, उसने औद्योगिक विकास के नाम पर बहुत कुछ करने का भाव मचाया। धारूहेड़ा में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और कहा गया कि यहां जो उद्योग लगेगे उन्हें 15 परसेंट सबसिडी देगे। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगे। लेकिन वहां क्या हुआ? धारूहेड़ा में सहगल पेपर मिल के नाम से एक उद्योग लगा। तापसे के लड़के का रूकमणी के नाम से गैस के सिलैन्डर का एक कारखाना लगा और इसी तरह से बहुत से कारखाने लगे। अध्यक्ष

महोदय, उस समय हरियाणा सरकार में जो कर्णधार बैठे थे, उनकी मिली भगत से जमीन ऐक्वायरकी गई। दो सौ रूपए गज की जमीन को 10-20 रूपए वर्ग गज के हिसाब से कारखानेदारों को थमा दिया गया। सबसिडी के नाम से ये लोग 15-15 लाख रूपया डकार गए। औद्योगिक विकास के नाम पर बड़ी लूट मचाई गई। अगर सरकार भ्रू हो जाएगा तो कर से छूट देंगे तो ये कारखाने सबसिडी का लाखों रूपया नहीं डकार पते। आज धारूहेड़ा जो दिल्ली से ज्यादा पास है और ने नल हाई वे नम्बर 8 पर है। मृतप्रायः पड़ा है, कुछ उद्योगों को छोड़कर। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का नया प्रस्ताव औद्योगिक विकास की गतिविधियों को तेज करने और उद्योगों के नाम पर सबसिडी लूटे जाने की प्रवृत्ति को दूर करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का लचीला रूख रहा है जब लकड़ियों के व्यापारियों को सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स से परे गानी हुई तो सरकार न उनके प्रतिनिधियों से मिल कर टैक्स वापिस ले लिये। अब कम्बलों पर टैक्स के बारे में व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत आ रही थी। व्यापारियों ने सरकार से गुहार की। सरकार ने लचीला रूख अपनाया और उनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास किया। अब सरकार ने एक लाख तक की कम्बलों की बिक्री को कर मुक्त कर दिया है। अभी डा० साहब ने कहा कि जो लोग अपना हिसाब किताब नहीं रखते थे, बुक्स प्रौपर नहीं रखते, उनके लिए फिलहाल कोई प्रावधान नहीं था इसलिए पैनल्टी लगाने का परन्तुम जोड़ा गया है अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि व्यापारी

जुर्माना से ज्यादा जेल की सजा से डरता है, वह कैद से डरत है। इसलिए जो व्यापारी अनियमितताएं करते हैं, जो व्यापारी कर की चोरी करते हैं उनकी जुर्माने की बजाए जेल में भेजने की व्यवस्था की जाए। इंसपैक्टरी राज से जनता को, व्यापारियों को मुक्त करवाने का हमारी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले वायदा किया था और इस बारे में कुछ कदम भी उठाए गये हैं लेकिन अभी काफी कमियां हैं, काफी ऐसे बहाने हैं जिनकी वजह से इंसपैक्टर्स व्यापारियों की दुकानों, प्रतिष्ठानों पर जाएंगे तो फिर वे अपनी फीस वसूल भी अवश्य करते रहेंगे। अभी यहां पर कहा गया कि जहा जहा हमने टैक्स की फीस कम की है, वहां आमदनी ज्यादा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब व्यापारी अपनी सेल्ज टैक्स की तारीख भुगतने आते हैं तो इंसपैक्टर उसकी बही का नहीं बल्कि उसकी जेब को देखते हैं 500, 1000 रूपया लेकर दस्ताखत कर देते हैं वरना तारीख लगाकर व्यापारी को तंग करते रहते हैं। इस कुप्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना कर इस समय लगा हुआ है अगर उस कर को ही पूरी तरह से वसूल कर लिया जाए तो उससे हमारे प्रदेश के राजस्व और खजाने में बढ़ोतरी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राव साहब बड़े काबिल और ईमानदार मंत्री हैं। मैं उनसे इसबात की आशा करता हूँ कि अधिकारी वर्ग में जो भ्रष्टाचार है, वे उससे

लड़ने में पहल करेंगे और यह जो व्यापारियों से 500, 1000 रुपये लेकर भुगतान की जो प्रणाली चली आ रही है, उसको समाप्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यादव साहब, अब आप बैठिये।

श्री रघु यादव: स्पीकर साहब, मैं बहुत जल्दी ही खत्म करूंगा। केवल दो मिनट मुझे और समय दे दीजियेगा, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ। कि जब हम अपने टैक्स का ढांचा तय करें तो कम से कम पड़ोसी राज्यों, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश वगैरह की तरफ भी ध्यान दे कि वहां पर टैक्स की क्या स्थिति है। वहां पर कर को क्या ढांचा है? अगर वहां पर टैक्स कम हो और हमारे ज्यादा हो तो क्या होगा? एक किस्म से स्मलिंग सी भुरू हो जाएगी। लोग दिल्ली वगैरह से कम कर का फायदा उठा कर के वही से सस्ती वस्तुएं खरीद करके हरियाणा में प्रवेश करेंगे। अगर राजस्थान में टैक्स कम है, तो वहां से खरीद कर हरियाणा में प्रवेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर मंगल सैन ने जो बोलते हुए रोहतक की एक इंडस्ट्री जोकि अन्डरवीयर और बनियाने बनाती है, का जिकर किया कि उसको प्रोत्साहन देने के लिये, ज्यादा से ज्यादा बिक्री को हरियाणा में प्रोत्साहित करने के लिये, हरियाणा सरकार के खजाने की बढ़ाने के लिये हमारी सरकार को इस तरफ

पूरा ध्यान देना चाहिए कि जो अैक्स हम लगा रहे है वह पडौसी राज्यों, दिल्ली, राजस्थान व हिमाचल से कम होना चाहिये। तभी हमारी बिक्री ज्यादा होगी, लोग हरियाणासे ही चीजे खरीदे देगा और उसका राजस्व हमारे हरियाणा को ही आएगा। इन बातों की ओर सरकार अव य ध्यान दे। अन्त में इस सं गोधन विधेयक का मै समर्थन करत हू और आपका धन्यवाद करता हुआ आपके आदे ानुसार अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द्र भार्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय आज राव राम नारायण जी ने हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय सं गोधन) विधेयक 1988 यहां पर प्रस्तुम किया है। मै उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं आपके माध्यम से मै राव साहब से कहूंगा कि जब हम न्याय युद्ध लड़ रहे थे तब हरियाणा के सभी वर्गों के लोगों ने उस न्याय युद्ध में भाग लिया था। उन्ही के कारण से आज हम यहां पर विराजमान है। हरियाणा के सभी वर्गों ने न्याय युद्ध के समय बड़ा सहयोग दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं हैं मेरे प्रदे ा के व्यापारी वर्ग ने भी, जब जब न्याय युद्ध भुरू हुआ या न्याय युद्ध की ओर से जब भी काल की गई, चहे वह बन्द की काल थी, चहो जन संग्रह की काल थी, चाहे कोई सम्मलेन करने की बात थी, या किसी नेता के सम्मान की बात थी, उसमें बढ चढ कर भाग लिया था ओर इस सरकार को बनाने मे उन का बहुत भारी हाथ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी लोकप्रिय सरकार आने के आद हरियाणा वर्ग, हरियाणा का किसान वर्ग बहुत खुश है। क्योंकि उनको इस सरकार से पूरी आशा है। कि यह सरकार उन्हीं के हितों के अनुरूप काम कर रही है लेकिन थोड़ी सी गलती या गलत अन्दाज के कारण, गलतफाहमी के कारण यदि हरियाणा का बहुत बड़ा वर्ग हमारे से नाराज होता है या वह ऐसा महसूस करकता है कि यह सरकार हमसे न्याय नहीं कर रही है तो ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जरूर कहीं न कहीं टैकल करने में गलती है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर 38 नम्बर का फार्म का जिक्र किया गया। उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आज के युग में संचार व्यवस्था बहुत तेज हो गी हैं पहले नारनौल का व्यापारी कलकता टेलीफोन पर बात करता था कि मुझे दो ट्रक माल भेज देना तो उसकी माल जल्दी मिल जाता था और अब गर उस पर 38 नम्बर फार्म की भार्त लगा दी जाएगी कि वह 38 नम्बर फार्म को साथ लेकर आए तो पहल वह नारनौल का व्यापारी कलकता जाएगा, वह फार्म भर कर देगा तब कही जा कर उसको माल मिलेगा। इस तरह से माल आने-जाने में तीन-चार दिन लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया बड़ी लम्बी है क्योंकि व्यापारियों का व्यापार टेलीफोन, टैलीग्राम तथा और माध्यमों से हात हैं कुछ दलाल होते हैं जो व्यापारी से आर्डर लेकर जाते हैं। कलकता और बम्बई से जो

दलाल आते हैं, वे व्यापारियों की डिमांड पूछते हैं कि आपको क्या क्या सामान चाहिए? वे उनका आर्डर लेकर आगे देते हैं और फिर व्यापारी को सामान सप्लाई होता है अब इस फार्म को इंट्रोड्यूस करने से व्यापारी को बड़ी दिक्कत हो गई है मैं चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए और इस फार्म को वापिस लिया जाए। अध्यक्ष महोदय जहां तक कम्बलों पर टैक्स लगाने का सवाल है, आज पानीपत के अन्दर कम्बल बनाने की बड़ी भारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। छोटे छोटे मजदूरों ने हैड लूमज लगा रखी है। आज पंजाब में आतंकवाद के कारण वहां के व्यापारी पानीपत में सैटल हो रहे हैं। यह बात ठीक है कि एक लाख रूपए की सेल की छूट दे रखी है लेकिन कपड़ा व्यापारी के पास कई आईटम्ज होती हैं, वह कैसे हिसाब रोगा कि एक लाख रूपए के कम्बल बिक चूके हैं? इससे तो केवल इन्स्पैक्टर को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि तुमने अकाउंट ठीक नहीं रखा। इस बहाने से केवल इन्स्पैक्टर की ही इंकम बढ़ेगी, सरार को वि 100 लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि कपड़े की कुल बिक्री में कम्बल की बिक्री का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा होगा। इसलिए मैं राव साहब से प्रार्थना करूंगा कि व्यापारियों की भावनाओं की ध्यान में रखते हुए कम्बल पर टैक्स न लगाया जाए। कम्बल के यार्न पर पहले से ही टैक्स लगा हुआ है, उसे आप बे 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि टैक्स बढ़ाना है तो यार्न पर बढ़ा सकते हैं परन्तु कम्बल पर से टैक्स वापिस ले लिया

जाए। इतनी प्रार्थना करते हुए मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपना स्थान लेता हूँ।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राव साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, इसके अन्दर हम थोड़ा सा संशोधन कराना चाहते हैं। इसमें कोई भाग नहीं है कि चौधरी देवी लाल जी के राज में व्यापारियों को बहुत सहूलियतें मिल हजै परन्तु इस संशोधन से थोड़ा सा जो कट हुआ है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फार्म 38 के बारे में सारे हरियाणा के व्यापारी परेशान हैं। कोई व्यापारी अगर बम्बई या कलकत्ता से फोन द्वारा या टैलीग्राम द्वारा माल मंगवाना चाहेगा तो जब तक वह फार्म नं० 38 नहीं भेजेगा, तब तक वह माल नहीं मंगवा सकेगा। फार्म भेजने में एक हफ्ता लग सकता है। और इस दौरान वह माल खत्म हो सकता है आज के युग के अन्दर एक हफ्ता काफी कम होता है इसलिए राव साहब से प्रार्थना है कि फार्म नं० 38 को वापिस लिया जाए। इसके साथ साथ जहां तक कम्पलों पर अक्सर लगाने का ताल्लुक है, कम्बल में ऐं नहीं अनेक चीजे आती है, इस बारे में किसी भी साथी ने नहीं बताया। जैसे भाल, दो गाला, चिकन और एम्ब्रायडरी की हुई साड़ी इसमें शामिल हैं इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा पानीपत के अन्दर छोटी छोटी खड्डियों पर धागे का काम करने वाले लोग हैं पिछले संवा या डेढ़ साल के अन्दर यह काम बहुत चमका है मैं इसका सारा श्रेय चौधरी साहब को दूंगा और श्री वीरेन्द्र सिंह जी का दूंगा जिन्होंने बिजली देकर

इतना कार्य बढ़ाया है। यह जो कम्बलों की इंडस्ट्री है, यह एक दो साल से ही बढ़ी है क्योंकि आतंकवाद के डर से व्यापारी अमृतसर से उजड़ कर पानीपत में आकर सैटल हुए हैं इदन लोगों की वजह से यह व्यापार चमका है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि छोटा व्यापारी जो खड्डी पर काम करता है उस पर टैक्स न लगाया जाए। धागे पर बे एक 2 प्रति मीटर की बजाए 3 प्रति मीटर टैक्स कर दिया जाए। इसके साथ ही जो मिल धागा बनती है और धागे से कम्बल तैयार करती है उस मिल के अन्दर ही कम्बल पर टैक्स वसूल कर लिया जाए लेकिन व्यापारी से कम्बल पर कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाए। हरियाणा के अन्दर कम से कम 40 परसेंट व्यापारी कपड़े का व्यापार करते हैं। भाल एक ऐसी चीज है जो 15 रूपए से लेकर 500 रूपए तक की मिलती हैं जहां पर एक लाख रूपए तक की कम्बल की बिक्री पर सेल्ज टैक्स की छूट दी जानी चाहिए। मेरी सरकारसे प्रार्थना है कि बाकी चीजों की भी एक लाख रूपए तक की बिक्री पर सेल्ज टैक्सकी छूट दी जाए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मिल धागा बनाती है और धागे से कम्बल तैयार करती है उस मिल के अन्दर ही यदि उसपर टैक्स वसूल कर लिया जाए तो व्यापारी इस परेशानी से बच जाएंगे। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कच्चे और बनियान है ये गरीब आदमी दो तीन रूपए से लेकर 5-6 रूपए तक खरीदते हैं जिनको गरीब मजदूरी पहनते हैं तो इन चीजों पर चार परसेंट सेल्ज टैक्स होना चाहिए। यह टैक्स हरियाणा प्रदेश के साथी लगते हुए दूसरे प्रदेशों में एक परसेंट या दो परसेंट ही है।

किसी भी प्रदेश में चार परसैट सेल्ज टैक्स नहीं है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पर सेल्ज टैक्स खत्म किया जाए यदि खत्म न किया जा सकता तो एक या दो परसैट कर दिया जाए क्योंकि उन चीजों को गरीब तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही मैं हौजरी के सामान के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। हरियाणा में जो हौजरी का माल आता है, उस माल को खास करके डेली पैसेंजर लोग लाते हैं। 125 रूपए, 150 रूपए और 200 रूपए तक की एक जर्सी आती है। हौजरी का जितना माल आता है वह या तो कारों से आता या उसको डेली पैसेंजर लोग ले कर आते हैं और यहां ला करसेल करते हैं यदि उस परचार परसैट सेल्ज टैक्स लगा दिया जाए तो उसको व्यापारी लोग अपने बही खाते में इन्दराज करेगे और उनको उसके बारे में किसी किस्म का कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हौजरी का माल या तो कारों में लाया जाता है या डेली पैसेंजर लोग ले कर आते हैं, उसकी सरकार चुगी भी नहीं मिलती है और न ही सेल्ज टैक्स मिलताहैं इन भाब्डों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री राव राम नाराण जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले जो फार्म नम्बर 38 है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: भाटिया साहब, फार्म नम्बर 38 के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। यदि इस बारे में आपके पास कोई नई बात कहने के लिए है तो बताएं।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: स्पीकर साहब, मैंने एक बहजुत ही जरूरी कहनी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यापारी को एक लाख रूपए का माल चाहिए और वह माल मंगाता है तो जब तक फार्म नं० 38 नहीं जता तो उस व्यापारी का माल नहीं जाता। इसका अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यापारी एक लाख रूपए का माल मंगाता है, वह माल खराब आ जाता है और उस माल को वह व्यापारी वापिस भेजना चाहता है लेकिन जब तक उस व्यापारी के पास फार्म नं 38 नहीं आ जाता है तब तक वह उस माल को वापिस नहीं भेज सकता। वह माल बीच में ही पड़ा-पड़ा खराब होता रहता है इसके अलावा एक बात यह भी है कि माल चालान पर जाता है तो वह माल तीन तीन महीने तक पास नहीं होता है। अगर व्यापारी 6वे महीने का बिल काट देता है, और वह माल अगर 7वे या 8वे महीने तक पड़ा रहता है और यदि उसका फार्म वैलिड होता है तो टैक्स नहीं लगेगा वरना उस पर टैक्स लगेगा। यदि वह माल रिजैक्ट हा'जात है तो व्यापारी उस माल को किस खाते में डाले? इसलिए मैं यह कहूंगा कि एक तो माल चालान पर नहीं जाना चाहिए और दूसरे इन फार्म नम्बर 38 को खत्म किया जाना चाहिए।

श्री भगवान सहाय रावत (पलवल): आदरणी अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 पर चर्चा चल रही है मैं भी इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसको बड़ी गहराई से देखने पर पता चलता है कि हमारी सरकार की और चौधरी देवी लाल जी की यह नीति है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाये, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई व्यापारी हो या चाहे कोई किसान हो इससे हमारी सरकार की नीति प्रतिलक्षित होती है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार यहां पर रखे और उन्होंने अपनी समझ के अनुसार यहां पर कुछ सुझाव भी दिए हैं और साथ ही इस बिल को प्रसंनीय बताया है। हमारी सरकार ने इस वित्त की धारा 6 में संशोधन करना, एक नई धारा 13 बी जोड़ना, धारा 14 तक संशोधन करना और धारा 36 की उपधारा (2) में परन्तुक जोड़ना, बड़ी गहराई से सोच विचार के बाद ऐसा किया गया है इसके लिए सरकार प्रसंसा की पात्र है। धारा 6 में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार जनवरी 1988 से पहले कम्बल कर मुक्त होते थे लेकिन बाद में इन पर टैक्स लगा दिया गया। जब व्यापारी लोगों के प्रतिनिधि मण्डल यानी कम्बल बनाने वाले चौधरी देवी लाल जी से मिले तो उनहोंने अपनी उदार नीति के तहत इसमें संशोधन कर दिया और अब एक लाख रुपये की बिक्री तक कम्बलों को टैक्स से छूट दे दी गई है यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि एक लाख से अधिक की बिक्री होने पर ही कम्बल पर टैक्स लगेगा। मेरे से पूर्व वक्ता श्री

रघु यादव जी ने इस बिल में धारा 13 बी को जोड़ना प्रोत्साहनीय कदम बताया है। चूंकि राज्य की हाल की घोषित उद्योग नीति के तहत जिन नए उद्योगों में जो माल 1 अप्रैल, 1988 के बाद बनेगा उसे कुछसमय के लिए कर मुक्त रख गया है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है हमारी सरकार की नए उद्योगों को बढ़ावा देने की एक नीति है जहां तक धारा 14 सवाल है इसमें कानूनी पेचीदगी को दूर करने का प्रावधान किया गया है इसे अलावा धारा 36 की उपधारा (2) में जो परन्तुम जोड़ा है जो एक अच्छी बात है। इसके जोड़े जाने से जो व्यापारी बेचे जाने वाले सामान की करन्ट बुक्स रही रखेंगे उन पर 2 हजार से 5 हजार रूपये तक जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। इस अमेंडमेंट से दो नम्बर का धन्धा करने वालों को सजा मिल सकेगी इसके साथ ही साथ मैं। एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि फार्म 38 के बारे में भी दुबारा से विचार किया जाये ताकि व्यापारी और सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत न आये। इन बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, जब से चौधरी देवी लाल जी ने राज सम्भाला है तब से लेकर अब तक इस सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया है। हमारी सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषित की है उद्योग नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एक टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी बनाई

हुई हैं इस टैक्स से इन ऐडवाइजरी कमेटी ने जो रिकमैन्डे इन की है। उन्हीं को इम्पीलमेंट करने के लिए यह विधेयक हाउस के सामने लाया है। इस विधेयक पर मैम्बरों ने बोलते हुए फार्म 38 के बारे में काफी कुछ कहा है मैं बताना चाहूंगा कि यह फार्म अकेले हमारे हरियाणा में ही लागू नहीं है बल्कि हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश में भी यह फार्म लागू है हरियाणा में यह फार्म कोई नया लागू नहीं किया गया है बल्कि पहले भी यह 38 नं फार्म लागू था। पहले कंसाईनी और कन्साईनर के हस्ताक्षर होने जरूरी नहीं होते थे। इस फार्म के लागू करने से कंसाईनी या कन्साईनर में से एक के हस्ताक्षर होना लाजमी होगा। जो लोग टैक्स की चोरी करते थे उन्हें जब विभाग वाले पकड़ते थे तो बच निकलते थे। यहां तक कि जब हम ट्रिब्यूनल के सामने जाते थे तो भी उस समय हमारा केस किसी के साईन नह होने की वजह से फेल हो जाता था। इसलि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फार्म 38 कायम रहेगा। कम्बलों के बारे में भी यहां पर जिक्र आया है जो लोग आगे टैक्सटाईल में डील करते थे वे लोग कम्बल भी रखते थे। इन पर टैक्स लगा दिया गया था। अब इस अमैडमेंट के जरिए उनको यह छूट दी जा रही है कि अगर कम्बलों की सेल एक साल में एक लाख के ऊपर होती है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा और एक लाख से कम सेल होती है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैं आनी बात समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं। कि इस विधेयक को पास कर दिया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 5

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 6

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 7

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 8

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Dr. Deputy speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Excise and Taxation Minister (Rao RAM Narain):

Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Spearker: Question is—

That the Bill be passed

The motion was carried

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रात 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

12.52 बजे

(तत्प चात् सदन दिनांक 25.08.1988 को प्रातः 9.30
बज तक के लिए स्थागित हुआ)